ascertain whether the member has the leave of the House. The Chair shall declare that since the mover has not pressed the motion, it shall be deemed to have been withdrawn by the leave of the House.

12.57 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF REHABILITATION INDUSTRIES CORPORATION, CALCUTTA

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (SHRI L. N. Mishra): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Rehabilitation Industries Corporation Limited, Calcutta, for the year 1965-66 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-clause (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 [*Placed in Library. See No* LT-990/67].

REPORT OF COMMISSION OF INQUIRY re COLLAPSE OF THREE HOUSES IN DELHI

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Commission of Inquiry into the causes of collapse of three houses in Delhi on the 15th August, 1966. [Placed in Library. See No LT-991/67].

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, on this subject, regarding the report of the Commission of Inquiry into the causes of collapse of three houses in Delhi, I would like to point out that whenever such a report is laid on the Table, the action taken on the Commission's report should also be let known to the House. I would like to know from the hon. Minister whether any action has been taken in this case, or, is it still under consideration.

Shri Vidya Charan Shukla: Action is under consideration, and we are in consultation with the Delhi Administration; after the action is completed, we shall definitely come before the House and report.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
EIGHTH REPORT

Shri Khadilkar (Khed): I beg to present the Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.57½ hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION—*contd.*

Mr. Speaker: Yesterday, we had taken 1 hour 35 minutes on the Demands for Grants under this Ministry. There is a balance of 8 hours 25 minutes. There are only one or two minutes more for the House to adjourn. So, instead of beginning the debate now, we shall begin it after lunch.

12.58 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Four Minutes Past, Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

DEMAND FOR GRANTS—*contd.*

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION—*contd.*

श्री भोला नाथ (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फूड एंड एग्रिकल्चर मंत्रालय की जो मांग है उन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

[श्री भोला नाथ]

इस सिलसिले में जिक्र करते हुए मैं आप का ध्यान अब के प्लैनिंग का जमाना शुरू हुआ उस की ओर ले जाना चाहता हूं। इस में कोई शक नहीं कि आजादी से पहले भी हिन्दुस्तान में कल्पना की गई थी कि हिन्दुस्तान की अकाल की प्लैनिंग हो और उस समय पं० जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से उस प्लैनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और मेरा खयाल यह है कि उसी की भूमिका में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो सन् 1950 के बाद यह कल्पना की गई कि हिन्दुस्तान के योजनाबद्ध विकास के सामने रख कर जनता को जागृत किया जाये। लेकिन मैं यह मानता हूं पन्द्रह वर्ष के तजुर्बे के बाद कि हम ने बड़ी भूलें की, और वह भूलें इस प्रकार की हैं जिन का समाधान जल्दी से जल्दी करने की आवश्यकता है। मेरा ख्याल तो यह है कि इमरजेंसी को, जिस को एक्सटेंड किया गया है इस बात के लिये काम में नहीं लाया जाना चाहिये कि हम किसी को सजा दें, बल्कि वह इस काम में लाई जानी चाहिये कि जो फड्स मिनिस्ट्रीज को दिये गए हैं, वह एकदम से फूड ऐंड एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री को दिये जायें। कारण यह है कि जो प्लैनिंग का नक्शा हमारे सामने आया है जो कन्से-प्शन हमारे सामने आया है वह बाहरी देशों का है योरपीय देशों का है। योरप में इंड-स्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ऐसे देशों में तरक्की हुई, मशीनरी की तरक्की हुई जिन के उप-निवेश थे जिन्होंने कालोनाइजेशन किया था। वे अपने देश में सामान बनवाते थे और कच्चा माल बाहर के देशों से लेते थे।

योरप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो असली खेती का नक्शा था हिन्दु-स्तान का उसे हम भूल गये। हमारे यहां कहावत है कि :

"उत्तम खेती मध्यम बान
अधम चाकरी भीख निदान।"

लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर इस का उल्टा हुआ है। हम चौथे स्टेज पर पहुंच गये हैं। हम भीख मांगने तक पहुंच गये हैं। हम को सब्सिडी मिलती है। हम पैसे की मदद देते हैं ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तीसरी बात की तरफ भी हम बढ़े हैं जिस को अधम कहा गया है। हम उस की तरफ ध्यान रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दिलायें। शहरों को भी देखिये गांवों की आबादी शहरों की तरफ चली आ रही है। मिलों और फैक्ट्रियों की नौकरियां बहुत बढ़ गई हैं। नतीजा यह हुआ कि हम घेराव की स्थिति में आ गये हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में इकट्ठे होने लगे हैं।

आज गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी जिन का हम पूरा ध्यान रखते हैं, घेराव की स्थिति में आ गये हैं। आज रेडियो बोल रहा था कि काफी घेराव गवर्नमेंट सर्वेंटस ने किये है। वह डी० ए० की मांग करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह डी० ए० क्या बला है। वह यह बला कि ऐग्रिकल्चर प्रोडक्शन कम होता है और यहां के लोग बैठे हुए हैं वह सब शहरों के हैं और वही के लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं। कभी ऐडजर्नमेंट मोशन लाते हैं, कभी काल अटेंशन नोटिस लाते हैं उन लोगों की पैरवी करने के लिये। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसानों से ही क्यों उम्मीद करते हैं कि वह अपना गेहूं आप को रुपये का 2 सेर बेचे। यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। न उस को चीनी सस्ती मिलती है और न सीमेंट सस्ता मिलता है न उस को टीन की चद्दरें सस्ती मिलती हैं। कल मैं सुन रहा था कि दुर्गापुर की प्रोडक्शन प्लेन की जो दूसरी स्टेज है उसे कम किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कारोगेटेड शीट्स गांवों को मिला करती थीं वह बन्द हो गई हैं। किसी काश्त-कार को नहीं मिल रही हैं। वह 3600 रु०

टन हो रही है । कोई चीज काश्तकार को मकान को ठीक करने के लिये नहीं मिल रही है । उन के पास छप्पर बदलने के लिये या मकान ठीक कराने के साधन नहीं है । लेकिन हम लोगों ने योजना इस तरीके से बनाई है कि हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । यह ठीक है कि चीन पाकिस्तान ने हमारी आखें खोल दी हैं । उस का नतीजा यह है हम लोग खेती की तरफ कुछ ध्यान देने लगे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम शहरों की तरफ से थोड़ा हट कर फूड ऐंड एग्रिकल्चर की तरफ ध्यान दें ।

अभी कुछ समय पहले श्री हनुमन्तैया भाषण दे रहे थे कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज को डी० ए० देने में गवर्नमेंट ने 53 करोड़ रुपये खर्च किये । अगर इतना ही राज्य सरकारें भी कर दें तो इस का यह मतलब हो गया कि 2 अरब रुपये खर्च हुए अगर इस 2 अरब रुपये को काश्तकारों को बांट दिया जाता तो हम देखते कि क्या स्थिति बनती है । मेरे पास खाद्य और कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है । उस में लिखा है कि दो लाख कुएं बनाये गये । मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं । मैं राजस्थान से आया हूं । राजस्थान में जैसलमेर का जो इलाका है उस में लगभग दस इंच साल में बारिश होती है । मैं इसको भी अच्छी तरह से जानता हूं कि जहां छोटे भी बांध बांध दिये गये हैं वहां अगर दस इंच भी साल में बारिश होती है तो उस इलाके में गेहूं पैदा होता है जिस को खड़ील कहते हैं । मेरे इलाके में पच्चीस इंच से ज्यादा साल में बारिश नहीं होती है । मैं खुद काश्तकार हूं, गेहूं पैदा करता हूं । मैंने इस ड्राउट में, विद-ड्राउट इरिगेशन और ड्राई कल्टीवेशन में करीब नौ सौ मन गेहूं पैदा किया है । क्या वजह है कि हम तरक्की ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं । वजह यह है कि मदद हम को नहीं मिलती है, पानी को रोकने के लिए मदद नहीं दी जाती है । मेरे खेत में भी एक भी कुआं नहीं है और न ही बिजली पहुंच पाई है ।

यह कहा जाता है कि दो हजार आबादी वाले जो कसबे हैं या चार हजार आबादी वाले जो कसबे हैं उन में बिजली पहुंच गई है । यह गलत बात है । मैं जानता हूं कि पांच पांच और सात सात हजार आबादी वाले कसबों तक में बिजली नहीं पहुंची है । काश्तकारों के साथ बिजली के मामले में भी बहुत बड़ा मजाक किया जाता है । मैंने इसके बारे में के० एल० राव साहब को भी कहा है और मैं कमेटी में भी हूं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि काश्तकारों को कहा जाता है कि रात को बिजली लो । अब आप देखें कि जनवरी और फरवरी के महीने में उनको रात के समय बिजली दीजाती है । यह वह समय होता है जबकि कोई रात में बाहर जाना पसन्द नहीं करता है । गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आप तरक्की दे रहे हैं, डी० ए० दे रहे हैं, उनके लिये आराम के रास्ते आपने हीटर लगा दिये हैं लेकिन काश्तकार से आप कहते हैं कि खेती के लिए वह रात को बिजली ले, जनवरी महीने में रात में बिजली ले और अपने खेतों में पानी दे । आप जानते ही हैं कि खेती खुए से होती है और खेती करने के लिए क्यारियां बनाई जाती है । जब एक क्यारी बन जाती है तो उसकी मदद से दूसरी क्यारी में पानी दिया जाता है । ऐसा करने के लिए काश्तकार को रात भर खेत में खड़े रहना पड़ता है अगर वह बिजली ले तो ।

मैं आपको चुनाव के दिनों का अपना अनुभव बतलाना चाहता हूं । जब मैं लोगों से वोट मांगने के लिए चुनाव के दिनों में गया तो सब से पहले वे यह कहने लगे कि हमारा इलाज करो तब वोट लेने आओ । हमारे यहां पहले डाक्टर भेजो फिर वोट लो क्योंकि हमारे बच्चे तो निमूनिये से मर रहे हैं और यहां कोई डाक्टरी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । इसी तरह से खेती की सहूलियतों के लिए उन्होंने मुझ से शिकायतें कीं कलक्टर लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट आदि जो

[श्री भोला नाथ]

होटलों का दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी इसका इन्तजाम है और जो मैंने अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन मुझे मालूम है कि मेम्बर्ज के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है लेकिन यह कैसा मजाक है कि काश्तकार को जनवरी और फरवरी के महीने में कहा जाता है कि वह रात को बिजली ले और उसका इस्तेमाल करे। डा० राव ने मेहरबानी करके मुझे इसका उत्तर यह दिया है कि यह हमेशा का फीचर नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि काश्तकार को रात में बिजली देने का कौन सा तरीका है? इस बात को आप हमें समझायें। इंडस्ट्री के लिये आप बिजली रात को दे सकते हैं, दफ्तरों के लिए रात को दे सकते हैं, आप क्यों काश्तकार को जाड़ों में रात में खड़े कर मारना चाहते हैं। यह उसके साथ मजाक है। इसको आप ठीक करने की कोशिश करें।

प्लानिंग का जो नक्शा मैंने आपके सामने पेश किया है उसको आप एक दम उलटा कर दीजिये खेती को उत्तम समझना आप शुरू कर दीजिये। इसको आप प्रथम स्थान दीजिये। ऐसा करने की आप मे हिम्मत है या नहीं है यह देखने वाली बात है। पार्लिमेंट सुप्रीम है और वह चाहे तो इस बजट को इस दृष्टि से देख कर इस में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। मैं चाहता हूं कि इसको आप देखें और आपका जो दृष्टिकोण है वह काश्तकार की तरफ ज्यादा होना चाहिये।

आज हम घेराव और पथराव की स्थित में हैं। पथराव तो जन संघ ने शुरू किया है और घराव की कम्युनिस्टों ने शुरू किया है। अब एक और घेराव होने वाला है। आपको यह राय दी जाती है कि लेवी वसूल करो, प्रोक्योरमेंट करो। किस लिए इसको किया जाय? यह कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल लेबर को खिलाने के लिए इसको किया जाए। जाहिर बात है कि एक तरफ तो वे इंडस्ट्रियल लेबर की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब लेवी वसूल की जाती है तो फिर नाराज हो जाते हैं और काश्तकार को भड़काते हैं कि लेवी मत दो। हम जानते हैं कि राजस्थान में जब लेवी वसूल करने की बात चली थी तो वहां पर गोलियां चली थीं। यह आसान बात नहीं है। एक मामली काश्तकार से कितना आप लेना चाहते हैं और उसके पास कितनी भूमि है यह भी आपको देखना होता है।

मेरा ख्याल है कि हर पचास व्यक्तियों के पीछे एक कुंए की योजना बनाई जा सकती है। एक एक कुआं अगर आप दे दे तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक और अकलमन्दी की बात यह कर दें कि ऊपर एक छोटा सा बांध बाध दे तो और भी अच्छा होगा। इसका लाभ यह होगा कि हमेशा वाटर लेवेल ऊपर रहेगा और काश्तकार के लिए यह पैरेनियल सोर्स आफ वाटर सप्लाई होगा। यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दो लाख कुएं आपने बनाये हैं। मैंने इसको फैला कर देखा है। 1965 मे आपने करीब 7.45 मिलियन टन अनाज बाहर से मंगाया है। अब इसको ले कर मैं राजस्थान के एवरेज से चलना चाहता हूं। दस टन एक कुएं से आसानी से अनाज पैदा किया जा सकता है। यह 270 मन के करीब होता है। हम 27 मन एक एकड़ में पैदा कर सकते हैं। अस्सी बीघे में भी नौ सौ मन पैदा किया जा सकता है। आप कहते हैं कि दो लाख कुएं आपने बनाये हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आठ लाख कुएं आप बना दीजिये और आप देखें कि अस्सी लाख टन की जो कमी है वह सिर्फ चार लाख कुओं से पूरी हो जाएगी। काश्तकार आप से कुएं मांगता है तो कोई मेहरबानी आप से वह नहीं चाहता

है। वह चाहता है कि उसको तकावी में रुपया दे दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को आप देते हैं मकान बनाने के लिए और तब से आप इस लोन को तीस साल में वसूल करते हैं। इसी तरह से आप किसान को तकावी दें और एक लम्बी अवधि में इसको वसूल करें तो आप देखेंगे कि किस तरह से पैदावार बढ़ती है। मकान बनाने के लिए शहर वालों को जो कर्जा दिया जाता है उसको तीस साल में वसूल किया जाता है। मैं भी एक कोआपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूं कंज्यूमर स्टोर का भी हूं। शहरों की जो हालत है उससे मैं भी वाकिफ हूं। आप जो शार्ट टर्म लोन किसान को देते हैं उसको उसे जुलाई अगस्त में देते हैं और मार्च में जल्दी से जल्दी फसल के मौके पर वसूल करना चाहते हैं छः महीने में उसको आप वसूल करना चाहते हैं। मीडियम टर्म का जो लोन है उसको आप दो ढाई साल मे वसूल करना चाहते हैं। जो लोग टर्म लोन है उसको आप सात आठ साल मे वसूल करना चाहते हैं। शहरी लोगों से मकान बनाने के लिए दिए गये कर्ज को तो आप तीस साल में वसूल करते हैं लेकिन इन से लाग टर्म लोन तक को सात आठ साल में वसूल करना चाहते हैं इस तरह से कैसे खेती की तरक्की हो सकती है। अगर आप चार पांच अरब रुपया कुएं बनाने के लिए दे दें तो किसान की परमानेंट इनकम भी बढ़ जाएगी और उसकी हैसियत भी बढ जाएगी।

लैंड रिफार्म की बात भी की जाती है। लैंड रिफार्म की बात बहुत आसान बात है। हमने राजस्थान में इसको करके देखा है। जमींदारों और जागीरदारों से जो जमीन हम लेना चाहते थे तब हमने दो बातें कीं। सब से पहले यह कहा कि बेदखली न हो। आप भी आर्डिनेंस पास कर सकते हैं कानून पास कर सकते हैं कि जो काश्तकार बैठा हुआ है उसे बेदखल न किया जाए। दूसरी बात हमने वहां यह की कि रैक रैंटिंग न हो लगान न बढ़ाया जाए। जैसे शहरों में होता है कि मकान और दूकान का किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है उसी तरह से काश्तकार के केस में रैक रैंटिग न हो। सिक्योरिटी आफ टैन्यार हो। इसके साथ ही साथ तीसरी बात यह की जा सकती है कि कुएं के लिए उसको तकावी दी जाए। यह तकावी ज्यादा नहीं होगी। मैंने कैलकुलेट किया है। दो लाख कुओं के लिए पांच हजार के हिसाब से एक अरब के करीब यह होती हैं। एक अरब कोई बडी बात नहीं है।

आप लोग यह पूछते हैं कि यह सकार कैसी है जो हर रोज टैक्स लगाती जाती है खर्च बढ़ाती जाती है। राजाओं का जब राज्य था तब रेवेन्यू और कस्टम्ज से वे काम चला लेते थे। लेकिन आज तो रोजाना तनख्वाहें बढ़ रही हैं पटवारियों की मास्टरों की क्लर्कों की बाबुओं की रोजना बढ़ रही हैं। साथ ही रिटायरमेंट की एज को 58 से घटा कर 55 किया जा रहा है और इस लिए किया जा रहा है कि नीचे के जो लोग हैं उनको तरक्की मिल सके। इस तरह से जो एक्सपेंडीचर है उसको आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। काश्तकार पूछता है कि वह क्या करें? उसका लगान बढ़ा दिया गया है वह कहा से पैसा लाये। आप ने 2600 या 2700 करोड के नोट छापे हुए हैं। यह आपकी रिपोर्ट मे है। 1965 की रिपोर्ट में है। उस में से आधा रुपया आप को चाहिये कि आप काश्तकारों के लिए एलाट कर दें उन के लिए रिजर्व कर दें। तब भी आप देखेंगे कि पैदावार बढ़ती है या नहीं बढ़ती है।

प्लानिंग का जो नक्शा है उसको आप एग्रिकलचर ओरियेंटिड बनायें, जउ से आप क्रान्तिकारी परिवर्तन करे। मुम्किन है कि आप पर आज जोर पड़ रहा हो। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि डांगे साहब का मुझ पर यह प्रभाव पड़ा है उन के द्वारा दिये गये भाषण का मुझ पर यह प्रभाव पड़ा है जब वह सोशलिस्टिक सोसाइटी की बात कर रहे थे तो उसका

[श्री भोला नाथ]

मुझ पर यह प्रभाव पड़ा है कि वह मार्क्सिस्ट सोसाइटी चाहते हैं। एक बार की बात है जिस तरह से बिहार मे प्रकाल पड़ा है और इस तंगी की वजह से लाल बहादुर जी ने जय किसान जय जवान का नारा लगाया था रूस में भी प्रकाल पड़ा था और तब वहां गोरकी ने भूख हड़ताल की थी। लेनिन ने तब उन से कहा था कि क्यू भूख हड़ताल कर रहे हो जब तक लोग भूखों नही मरेंगे तब तक क्रान्ति नही होगी। इसलिए आप इस व्रत को छोड़ दो और क्रान्ति लाओ। हमारे डांगे जी भी चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा भूखों मरें और यहा क्रान्ति हो। वह सारे रुपये को खेती से हटा कर इडस्ट्री की तरफ ले जाना चाहते हैं शहरों की तरफ से जाना चाहते हैं और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर घेराव और पथराव करवाना चाहते हैं और सरकार को घेराव में डालना चाहते हैं। इन सब से बचने का रास्ता यह है कि आप क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनायें और खेती पर चौथी योजना मे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिमेंट आप कुएं बनाने के लिए और खेती के काम के लिए दें। रत्ती भर सिमेंट भी आप बड़ी बड़ी दस बीस मंजिली इमारतों के लिए न दें। आपको यह पता होगा कि सिविल का कोटा सिमेंट का सत्तर परसेंट है और एग्रिकल्चर का शायद तीस परसेंट है। जो किसान है उसको सिमेंट समय पर नही मिलता है तो उसको तकावी भी समय पर नही मिलती है और अगर तकावी नही मिलती है तो सिमेंट भी नहीं मिलता है। इस वास्ते इन दोनों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। तकावी और सिमेंट उसको समय पर मिलना चाहिये। इन सब बातों पर आपका ध्यान जाए यही मेरा निवेदन है

Shri N. R. Patil (Bhir): *Spoke in Marathi**.

श्री राम किशन (होशियारपुर) : इस में कोई शक नही है कि जब से यह फूड और एग्रीकल्चर के विभाग को बाबू जगजीवन राम जी ने संभाला है उन्होंने काफी प्राग्रसिव स्टेप्स लिए हैं। लेकिन इस देश के इतिहास मे जितनी इस वक्त गम्भीर स्थिति फूड और एग्रीकल्चर की हो गई है इतनी शायद कभी देखने में नहीं आई अभी जो रिपोर्ट शाया हुई है डिप्टी स्पीकर साहब उस को देखने से पता चलता है कि पिछले एक साल मे इस सारे देश ने जितना रुपया एक्सपोर्ट से कमाया था उतने रुपये का हमने फूड ग्रेन्स का इम्पोर्ट किया है। इस पिछले एक साल में कोई 523 31 करोड़ रुपया हमारा फूड ग्रेन्स के इम्पोर्ट के ऊपर खर्च हुआ है। पिछले 20 साल में इतना रुपया कभी इस फूड की इम्पोर्ट पर खर्च नही हुआ। सिर्फ यही नही बल्कि इस के अन्दर हम ने 105 64 करोड़ रुपया सिर्फ फ्रेट चार्जेज के ऊपर खर्च किया है। इस के माने यह है कि अगर एक रुपये का अनाज मगाते है तो उस के लिए 28 नये पैसे जहाज का किराया देना पड़ता है। इस से पता चलता है कि कितनी गम्भीर स्थिति आज देश के सामने इस फूड के मामले में है।

एक और चीज जिस की तरफ मैं हाउस का और आप का ध्यान दिलाना चाहता हू डिप्टी स्पीकर साहब, यह है कि इस सारे देश के अन्दर पिछले एक साल के अन्दर जहा हमने 10.36 मिलियन टन्स खुराक बाहर से मंगवाई है उस के मुकाबिले मे हमारे सारे देश के अन्दर प्रोक्योरमेंट कितना हुआ है ? प्रोक्योरमेंट के लिहाज से देखें तो हिन्दुस्तान की आजादी के समय से लेकर

*The Member did not furnish a translation of his speech in Hindi or English.

47 से ले कर इस वक्त तक पिछले 20 साल के अन्दर हम ने पांच फूड ग्रेन एन्क्वायरी और फूड ग्रेन पालिसी कमेटी बिठाई । एक कमेटी प्रीइंडिपेंडेंस डेज में बंगाल का कहत जब पड़ा था तब बिठायी थी और चार उस के बाद बिठायी हैं पिछले 22-24 साल के अन्दर प्री-इंडिपेंडेंस से लेकर इस वक्त तक । सिर्फ ब्रिटिश राज के जमाने में 42-43 के बाद एक बार कोई 5 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट हुआ था उसस के बाद 64 के अन्दर जो हमारा सब से अच्छा साल आया था उस के अन्दर 4 मिलियन टन्स प्रोक्योरमेंट हुआ । लेकिन वह भी सारे का सारा 65-66 में खत्म हो गया । तो प्रोक्योरमेंट के लिहाज से सब से पीछ हैं । और यह जो नया साल शुरू हुआ इस के पहले क्वार्टर मे 22 लाख टन का इम्पोर्ट हम ने किया । जहा तक स्टेट्स का ताल्लुक है सारे देश के अन्दर इस वक्त तक कुल 27 लाख टन सारे का सारा प्रोक्योरमेंट हुआ है । तो प्रोक्योरमेंट के लिहाज से हिन्दुस्तान पीछ जा रहा है । इम्पोर्ट के लिहाज से हम आगे बढ रहे हैं । अगर हमारी यही हालत रहती है तो हिन्दुस्तान की एकोनामी की क्या हालत होगी ? मुझे इस बात की हैरानी होती है कि जितने भी अपोजीशन बेचेज पर हमारे दोस्त बैठे हैं हरएक आदमी यहा आ कर गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस के लिए कोसता है । लेकिन किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नही दिया है । इस बार अभी थोड़ दिन हुए जबकि यू० पी० के चीफ मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ने स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने यह कहा था कि इस बार यू० पी० के अन्दर जितना बम्पर काप हुआ है उतना पिछले 18 साल के अन्दर नहीं हुआ है । 45 लाख टन अनाज वहां हुआ 33 लाख के मुकाबिले में । 12 लाख टन ज्यादा हुआ । लेकिन प्रोक्योरमेंट उस के मुकाबिले में कितना हुआ है ? पंजाब के अन्दर इस बार इतना बम्पर काप हुआ जिस की कोई हद नहीं है लेकिन उस के मुकाबिले में इस वक्त तक कितना प्रोक्योरमेंट हुआ है ? 2.5 लाख टन सारा प्रक्योरमेंट हुआ है । सी तरह बाकी जगह आप देखें । नान-कांग्रेस गवर्नमेंटस हैं या दूसरी हैं, प्रोक्योरमेंट उस के मुताबिक ठीक नही हो रही है । एक्सपोर्ट में सारा रुपया जा रहा है कहीं फ्रेट चार्जीज के अन्दर और कही दूसरी चीजों खुराक खरीदने में जा रहा है । तो हिन्दुस्तान की एकोनामी जिन हालात में है उस में हम क्या कर सकेंगे कुछ कहा नही जा सकता । और सिर्फ यही नही जो मैं केवल दो प्रान्तो की बात कर रहा था यह जो व्हीट जोन है नार्दर्न जोन का अगर हम पिछले तीन चार साल का सारा देखें 64-65 और 65-66 के मुकाबले में इस बार मार्केट के अन्दर व्हीट 14 परसेंट कम आया है । राइस 7 परसेंट कम आया है । इस के मानी यह हैं कि अनाज मोजूद है लेकिन किसी जगह छिया पडा है । होर्डर्स के पास छिपा पड़ा है, जमीनदार के पास छिपा पडा है या ट्रेडर्स के पास छिपा पड़ा है किस जगह छिपा पडा है मैं नही जानता । लेकिन एक बात साफ है कि बम्पर काप होने के बावजूद अनाज मोजूद होने के बावजूद वह मार्केट में नही आ रहा है और हमारे हिन्दुस्तान के सारे नेशनल एग्जिस्टेंस को एक चैलेंज सा हो रहा है । हमारी एकोनामी को एक चैलेज मिल रहा है । मालूम नही हम किस हद तक उस को एक्ससेप्ट कर पाते हैं और मुकाबला कर पाते हैं । इस के मुकाबिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया का जहा तक ताल्लुक है सब्सिडी बढ़ रही है । 119 करोड़ रुपये से 130 करोड़ रुपये तक सब्सिडी आ गई है एक साल अन्दर । इस तरह कब तक यह चलेगा ? इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब आप के मार्फत मैं अपने मिनिस्टर साहब से और हाउस से कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है कि इस सवाल को हम एक नेशनल प्वाइंट आफ व्यू से देखें । इसे प्राविंशियल प्वाइंट आफ व्यू से या दूसरे किसी प्वाइंट आफ व्यू से न देखें । पिछले सात आठ साल के अन्दर जितनी चीफ मिनिस्टरों

[श्री राम किशन]

कान्फरेंसेज़ हुई हैं और इस जनरल एलेक्शन के बाद दो चीफ मिनिस्टर्स कान्फरेंस हो चुकी हैं इनमें जितने भी फैसले हुए उन पर कितना अमल हुआ है। अभी मैंने फूड ग्रेन्ज पालिसी कमेटी की बात कही उन के जितने डिसीजन्ज हुए हैं चीफ़ मिनिस्टर्ज के जितने डिसीज्न्ज़ हुए हैं अगर उन में से एक डिसीजन पर भी अमल हो जाता तो शायद हिन्दुस्तान का उस से ज्यादा भला होता।

नवम्बर, 1966 मे चीफ मिनिस्टर्ज की कान्फ्रेन्स हुई, जिसमे उन्होंने फैसला किया कि हम चार सालों के अन्दर 1 करोड़ 20 लाख टन प्रोक्योर कर के हिन्दुस्तान का एक बफर-स्टाक बनायेंगे। अभी 8–9 अप्रल को चीफ मिनिस्टर्ज की कान्फ्रन्स हुई, उस के अन्दर भी कुछ फैसले किये गये–उस मे एक फैसला उन्होंने यह किया कि हम सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इन्टेंसीफाई करेंगे, माइनर इरिगेशन पर जोर दिया गया। गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ने इस के लिये 120 करोड रुपया दिया लेकिन चीफ मिनिस्टर्ज कान्फ्रन्स की जो हाल की कार्यवाही निकली है उस से पता चलता है कि जहा तक स्टेट्स का ताल्लुक है वह कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नही हैं और जो हिस्सा स्टेट्स को 120 करोड़ रुपये में अदा करना था, वे उस को अदा करने को तैयार नहीं हैं। लैण्ड रेवेन्यू खत्म हो रहा है, प्रक्योरमेन्ट हो नही रहा है, आखिर किस तरह से हम उस के मुताबिक सारी चीजों को कर पायेंगें, समझ में नही आता है। इस लिये, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब अब वक्त आ गया है कि हम इन सारी चीजों पर गौर करें कि आखिर हम जा कहां रहे हैं कहां हम को पहुंचना है ?

अब हमारी क्या हालत है ? हमारे यहां जितनी लैंड है, जितनी कल्टीवेशन लैंड हम यूज कर सकते हैं—इस वक्त 43 परसेन्ट लैंड है जिस में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं—दुनिया के किसी मुल्क में इतनी धरती मे काश्त नहीं होती है, लेकिन उस के बावजूद भी हालत क्या है। ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारे पास है, 6 करोड़ फमिलीज़ का कृषि का काम करती हैं लेकिन उस के मुकाबले जहां तक ईल्ड का ताल्लुक है यह दुनिया में सब से कम है। मैं इस की दो मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं—जापान, एक ऐसा देश है, जिसमे ज्यादातर पहाड़ हैं और इसकी वजह से वे अपनी सारी जमीन को काश्त मे नही ला सकते हैं, 16 4 परसेन्ट जमीन को वे काश्त के अण्डर लाये हैं, वहा की सिर्फ 33 परसेन्ट आबादी काश्त करती है, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, आप यह सुन कर हैरान होंगे कि 16 4 परसेन्ट जमीन पर काश्त करने वाला जापान चावल पदावार मे सब से आगे है, उस की चावल की पदावार दुनिया मे सब से ज्यादा है। सारे जापान के लिये सैल्फ सफिशियेन्ट होने के बावजूद वह सरप्लस मुल्क है।

अमरीका की क्या हालत है। वहां पर एक किसान इतना पदा करता है कि अपने अलावा 25 आदमियों के लिये पूरी तरह से खुराक देता है, तीन आदमी जो विदेश मे हैं उन को फीड करता है और फिर भी बाकी बचाता है। लेकिन हिन्दुस्तान मे 20 साल के बाद यह हालत है कि 7 किसान रात-दिन करने के बावजूद भी 10 आदमियों को फीड नहीं कर सकते हैं।

मैंने जापान का जिक्र किया, लेकिन आप हिन्दुस्तान में देखिये-चाहे पंजाब का सिंचाई का इलाका हो या यू० पी० का तराई का इलाका हो, ये इलाके हमारे यहां सब से ज्यादा चावल पैदा करते हैं, लेकिन इन जापान के मुकाबले तीन गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल कर के भी उतना चावल पैदा नहीं कर सके,

जितना जापान हम से एक-तिहाई पानी इस्तेमाल कर के पैदा कर लेता है। इस की वजह क्या है ? हमारे यहां वाटर का यूटिलाइजेशन एफिशियेन्ट नहीं है कम है और पानी का नुक्सान होता है ।

जहां तक खाद का ताल्लुक है, हमारे यहां दुनिया के मुकाबले मे सबसे कम (फी एकड़) इस्तेमाल होती है, अगर हम सारी दुनिया की एव्रेज ले तो दुनिया के मुकाबले मे खाद का इस्तेमाल कर पाते हैं। आदमी के लिहाज से जमीन के लिहाज से टैकनीक के लिहाज से सब कुछ हमारे पास है लेकिन उस के बावजूद भी हालत यह है कि 20 साल मे हमारी हालत मे कोई तरक्की नही हुई, हम नीचे की तरफ हो जा रहे हैं। इस की क्या वजह है ? इस के मायने साफ है कि हमारे यहा कुछ खराबी हैं बुनियादी खराबी है, बेसिक खराबी है, जिसको हम दूर नही कर पाये हैं। एक सब से बडी खराबी यह है कि आज दुनिया के जो बडे बडे मुल्क हैं जापान, कोरिया, अमरीका वगैरह, वे जिन मैथड्स का इस्तेमाल अपने यहा एग्रीकल्चर मे करते हैं, हम उन मैथड्स का इस्तेमाल अपने यहा नही कर पाते हैं। जब तक इस देश मे एग्रीकल्चर के अन्दर तरक्की नही होगी, यह देश आगे नही बढ़ सकेगा। असल बात यह है कि आज की गवर्नमेन्ट को एग्रीकल्चर के मसले को एग्रीकल्चर के तौर पर नहीं, बल्कि इण्डस्ट्री के तौर पर कन्सीडर करना होगा, बल्कि उस को पूरी तरह से इण्डस्ट्रीयलाइज करना होगा, तब जा कर सारा काम चल सकेगा।

जब मैं इस बात का जिक्र करता हू कि अमरीका, जापान या दूसरी एडवान्स्ड कन्ट्रीज ने किस तरह से इस सारे सिलसिले को चलाया है, तो मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर की जो नई स्ट्रैटिजी हमारी गवर्नमेन्ट, हमारे फूड मिनिस्टर साहब अपना रही था रही हैं, मैं उन खास-खास चीजों पर भी, जो अमरीका, जापान या दूसरी एडवान्स्ड कन्ट्रीज ने अपने अख्तियार की हैं, तवज्जह देंगे वे हैं—

adoption of machinery and technological inventions in farming,

increasing application of scientfic and technological methods to agriculture;

agricultural education, heavy use of fertilisers;

mechanisation, improved varieties of crops and livestocks, better seeds better irrigation and drainage, better methods of controlling weeds and pests Implementation of research result in forming

अब आपकी मारफत, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहा हू हम ने इस देश के लिये जिस तरह का ध्येय बनाया है, जिस तरह का टारगेट बनाया है कि सन् 1970–71 तक हम इस देश को सेल्फ सफिशियेन्ट बनाना चाहते है, सरकारी आकड़ो के मुताबिक जितनी हमारी प्रोडक्शन है या जितना खाना हम खाते है, उस मे 24 मिलियन टन की एडीशनल जरूरत होगी। इस नई हाई-ब्रेड-वैरायटीज की मदद से 1970–71 तक, जो फैक्ट्स एण्ड फिगर्स दी गई है, उन के मुताबिक 32 5 मिलियन एकड़ जमीन से हमे इन नई वैरायटीज को ले जाना है। अगर हम इस काम को पूरी तरह से सरंजाम दे, तो फिर 24 मिलियन टन ही नही, बल्कि उस के अन्दर 25.5 मिलियन टन हम ज्यादा पैदा कर सकेगे। अब सवाल है कि किस तरह से कर सकते हैं ? इसके लिये तीन-चार शर्तें हैं और इस मिनिस्ट्री को उस चेलेंज को कुबूल कर के उस को करना होगा—सब से जरूरी चीज तो यह है कि जहां तक फर्टिलाइजर का ताल्लुक है, मिनिस्ट्री को देखना होगा कि वह फर्टिलाइजर

[श्री राम किशन]

की पूरी तरह से देने के लिये तयार है या नहीं 1970-71 तक जितने फर्टीलाइजर की जरूरत है, जितना आज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 20 लाख टन नाइट्रोजन की और जरूरत होगी, इसी तरह और भी चीजें जैसे फास्फेट आफ पोटेशियम है इनकी जरूरत होगी, जिसको पूरा करने के लिये 487 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 194 करोड़ रुपया फौरन-एक्सचेन्ज आपको देना पड़ेगा, इन सब का आपको इन्तजाम करना होगा । अगर 1970-71 तक के ध्येय को पूरा करना चाहते हैं तो फिर जहां तक फर्टिलाइजर का ताल्लुक है, देश के किसानों को यकीन दिलाना होगा कि इस अर्से में उन को जितना फर्टीलाइजर चाहिये, वह आप मुहैया करेंगे । अगर आप फर्टिलाजर देने को तैयार नहीं होंगे तो यह सिलसिला चलने वाला नहीं है । इस लिये मैं आशा करता हूं कि आप इस तरफ पूरी तवज्जह देंगे ।

आप 1969 में महात्मा गांधी की सेन्टेनरी मनाने जा रहे हैं । आज जिसकी बदौलत हम यहां पर बैठे हुए हैं उसके मुताबिक फैसला करें कि हम हिन्दुस्तान को सेल्फ-सफिशियेन्ट बनायेंगे और उसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होगी हम उनको मुहैया करेंगे । जिन चीजों की खास तौर पर आपको जरूरत होगी मैं उन चीजों की तरफ अब आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं—वे 10-12 चीजें हैं मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप उन पर पूरी तरह से अमल करें, ताकि हमारा यह सिलसिला तेजी से चल सके—

1. गारण्टीड प्राइस पालिसी आप किसानों को पूरी तरह से यकीन नहीं देते हैं कि आज क्या प्राइस होगी और कल क्या प्राइस होगी । आपको एक गैरन्टीड प्राइस पालिसी एनाउन्स करनी होगी, ताकि किसानों को पता चल जाय कि उन को 1970-71 तक क्या प्राइस मिलेगी ।

2. स्पेशलाइज्ड एक्सटेन्सिव एण्ड टैक्निकल एडीकल्चर सर्विस—इस काम को थोड़ा जोर से करना होगा । सारे एक्सटेन्सिव प्रोग्राम को स्ट्रेन्थन करने के लिए इस पर जोर देना होगा । कम्यूनिटी ब्लाक और ग्राम सेवकों को यह भी मालूम नहीं है कि किसानों को किस तरह का नौलिज देने की जरूरत है, कहां से इन-पुट्स आयेंगे इनकी तरफ खास तवज्जह देकर इनको स्ट्रेन्थन करना होगा ।

3. फर्टिलाइजर—इस के लिये मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है ।

4. एफिशियेन्सी इन यूटिलाइजेशन आफ वाटर—इस के लिये डिटेल में न जाते हुए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कैलेफोर्निया ने अपने यहां वाटर सिस्टम का कोड बनाया है उस को आप पूरी तरह से महैलजर रखें और देखें कि एक-एक कतरा पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके ।

5. फार्मर्ज ट्रेनिंग

इनके अलावा दो बातें और हैं । आज हमारे देश में जिस तरह से यह अंधा चल रहा है यानी जोन का जो सिस्टम है उस ने भाई से भाई को जुदा कर दिया है । हिमाचल की अजीब हालत है मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी—होशियारपुर की यह हालत है कि जिन पहाड़ों ने डैम दिये जिन पहाड़ों ने पानी दिया, जिनकी मदद से सिंचाई होती है, लेकिन उनको उस के मुताबिक अनाज नहीं मिलता । सिर्फ यही नहीं मैं आपसे पंजाब का जिक्र करता हूं । नंगल डैमके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने एक बैरियर लगा दिया है । नंगल डैम के उधर कोई 80 रु० क्विन्टल गेहूं मिलता है लेकिन जहां पर नंगल फैक्ट्री है वहां 150 और 160 रु० क्विन्टल भी गेहूं नहीं मिलता । हिमाचल प्रदेश की भी यही हालत है । इसलिए मैं आपके जरिये से मिनिस्टर साहब

से अर्ज करना चाहता हूं कि वक्त आ गया है जब कि एक नेशनल कमिशन आन फूड सेल्फ-सफिशिएन्सी कायम किया जाय जिस के सदस्य पूरी तरह से एक्सपर्ट्स हों। और एकानमिस्ट्स हों और सब चीजों को देख करके वह तय करे कि फूड जोन्स किसी शक्ल में कायम रखने हैं या नहीं रखने हैं। हिन्दुस्तान की यकजहती इंटेग्रेशन के खयाल से आप इस को देखिये।

आज अजीब हालत हो रही है कि जो 10 परसेन्ट अनाज बाहर से आता है उसकी प्राइस पर हमारा कंट्रोल है लेकिन जो 90 परसेंट अनाज हिन्दुस्तान मे पैदा हो रहा है उसकी प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है। 1962 में चाइनीज ऐग्रेशन के बाद जो नारा लगाया गया था कि प्राईस-लाइन इज दि लाइफ-लाइन आफ दि नेशन लेट अस होल्ड इट। कहा गई वह प्राइस लाइन जो कि हमारी लाइफ-लाइन थी ? वह और भी बढ़ती जा रही है।

इस लिये मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि अब वक्त आ गया है कि हम इन सारी चीजों पर गौर करे। अगर हमको फूड के अन्दर सेल्फ सफिशिएन्सी हासिल करनी है तो जिन जिन चीजों की जरूरत है किसान को किसान को वह सब चीजें दें। इस देश की इएकानमी को बचायें और देश के भविष्य को भी उज्ज्वल करने की कोशिश करे।

Shri H. P. Chatterjee (Krishnagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, our total import in the third Five Year Plan was to the tune of Rs. 1,033 crores, of which the PL-480 imports were Rs. 849 crores. In 1966 alone, we had imported 10.36 million tons valued at Rs. 523·31 crores, of which PL-480 imports were 80·3 lakh tons valued at Rs. 343·1 crores. We pay 35 dollars for each ton of food that is being shipped from the USA.

Our production in 1964-65 was 89 million tons; 1965-66, 72 million tons; 1966-67, 76 million tons. If there was no drought, we assumed that we would get in 1966-67, 90 million tons. Our requirement at the end of the fourth Five Year Plan is 120 million tons. That is, we shall have to produce six million tons more per annum. But in the case of our agriculture, only a stepmotherly attention is given. The third Five Year Plan laid stress on agriculture, but plan priority is not observed by the States Once they go to the States, the plan priority is shelved and thus the planning papers became only a farce.

In 1964, our national income was Rs. 16,630 crores. We got from agriculture Rs. 7,462 crores, that is, nearly half. Yet, we spent only 10 per cent on agriculture. For agricultural education, we spent Rs. 30 crores as against Rs. 142 crores on technical education. That is also 10 per cent. For research on agriculture we spend very little of science budget. In Australia and New Zealand. 45 per cent of the total science budget is spent on agricultural research. Our community development programme is an American pill that we have swallowed We have imported sahebs into the villages, non-technical men, who know nothing of agriculture. They cannot advise 66 millions of agriculturists spread over 5 6 lakh villages.

What to do? We shall have to produce 120 million tons at the end of the fourth plan. We must go in for intensive cultivation, because we have no land for agriculture It is not my saying. I initiated the discussion on the agriculture budget in 1963 and in his reply on 21st March, 1963, Shri S. K Patil said:

"In India, not now, but for all time, to come, there is no land for agriculture. Even more, if any land is available, I shall rather use it for forests and not for agriculture. If there is total destruction or diminution of forests, agriculture can never make

[Shri H. P. Chatterjee]

any progress. In our country, forests should be somewhere about 50 per cent at least. It has gone down to 20 per cent; sometimes it is 18 to 23 per cent. I do not know what is the correct figure. If there is any possibility of utilising more land for forests, I as Minister of Food and I think even the Minister directly in charge of forests, Dr. Ram Subhag Singh—we are of the opinion that more land should be given to forests in order to stabilise the condition of agriculture and no land should be taken away."

Profession and practice are different. Taking 1950 as the base year with 100, we find that cultivated land has gradually gone up in 1963-64 to 122.7, i.e. an increment of 22·7 per cent. The percentage of our cultivated land is about 47. We should have forests of about 33 per cent. We should reduce the cultivated land to 33 per cent. That is the forest policy which we have accepted. But in actual practice, what do we do? We go on increasing production in marginal soil and thereby we harm our agriculture. God should not be blamed for the drought, but we should be blamed because we cut down all the forests. Forests bring in clouds because of the transpiration they do But we destroy the forests like anything. Many civilisations in the past have perished because they have destroyed forests for colonisation and for agricultural land. This is a historical fact. Here is a book published by UNO—*Rape of Earth*—which shows clearly how civilisation in Persia, North China and Mesapotamia perished because they cut down forests. Trees are the emblem of humility. They also give shade, even when we cut them down. But in our vandalism, we cut down the trees. We have created an imbalance in nature. I had toured in Palamau district and Hazaribagh district. You cannot get a drop of water there because there is no forest. Where there is forest, you will find water. Otherwise the river beds are also dry.

15 hrs.

Anyway, Sir, we must remember that in Japan 67 per cent is under forest, in the U.S.S.R., it is 45 per cent and in Europe it is 41 per cent. Ours is the lowest in the world. We have 805 million acres of land in India and of that 138·5 million acres are under forest. That comes to only 17·2 per cent.

India is in the grip of soil erosion. One hon. friend from Punjab was saying how chos and gullies have formed there. In India 200 million acres are under soil erosion. That means one-fourth of our total land is under soil erosion. In the Siwalik foot-hills of Hoshiarpur District in Punjab, forest has been cut down. What happened? Chos and gullies have appeared in that most fertile land due to soil erosion and it just expands in geometrical progression. In 1852, in the Siwalik foot-hills, in Hoshiarpur, Punjab, gullies were 75 square milles It went up to 1700 square miles nearly ten times by 1939, within less than a century. You also know that in Chambal ravines, which are now the bandits home, and also in the Etawah ravines, the Indo-Gangetic plains, about 6 million acres of land can be reclaimed and formed into very good cultivable land. It may be converted into our granary. So, not only here but in all places soil erosion comes in.

Our late Chief Engineer of the Central Water and Power Commission, Shri Man Singh, in his Flood Committee Report has written:

> "If soil and water conservation programme is postponed for one year at least half million acres of good land will be lost for ever."

Now I come to one main thing and that is irrigation. If we go in for intensive cultivation we must go in for irrigation. Irrigation is the first thing necessary and we are losing our irrigation potential like anything. Our outlay in river valley projects including power, irrigation and other things is about Rs. 3000 crores. All these are in danger. What will happen to these in the near future nobody can say. Our experts say that the Bhakra dam where we have spent more than Rs. 200 crores is dying. I have got here an article by Sardar Partap Singh, IFS, Retired Forest Officer I do not want to quote everything It was published in *Statesman* in August 19, 1965 under the heading: "Saving Bhakra Dam from premature death—Forest conservation the only effective method—Bhakra Dam is dying". This is what a just retired manager of Bhakra Dam said on Bhakra Dam at the Simla Flood Control Seminar in 1962. Silting is 67 per cent more than was calculated. So, something must be done about it What is the good of going in for new irrigation when we cannot save our existing projects?

Mr. Deputy-Speaker: He should try to conclude.

Shri H. P. Chatterjee: I have 26 minutes because I am the only speaker for the Progressive Group. If you disturb me it will be difficult for me to continue my speech I would rather sit down. This is my subject. Further, I have not spoken for more than 7 minutes. I have seen the clock.

Mr. Deputy-Speaker: He has taken 14 minutes. If he wants to exhaust the whole time of his Group, I have nothing to say

Shri H. P. Chatterjee: Since there are so many members in the Progressive Group, after calculation 26 minutes have been allotted to us. I am the only speaker for my Group. If I am not given that much time, it is better that I go out from Parliament, it is better for me to resign. When I was an Independent, I had no *locus standi*; I was a second-class Member here. Now, when I join a Group, then also no time is given to me. Then, how can I work? I shall speak for 26 minutes of my time and 4 minutes from you, half an hour in all. Please, do not disturb me. This is a very important subject.

We have spent so much money on these projects and now our Ministers are sleeping over them. I have seen that they have become golf courses. If you come along with me to Tilaya, Mython and to other dams in winter and see the dried up live storages, you will find that they are just lying as golf courses You cannot see any vegetation there on the catchment area What is the good of creating new irrigation dams and all that, when we cannot check silting up of the existing dams because of soil erosion? Our Parliamentarians should know that this is wrong.

On account of the shortage of time, I am not able to refer to soil erosion in detail. Soil erosion is not static; it is dynamic Erosion varies as the square and the transported material as the sixth power of velocity of water flow. Suppose the velocity is increased ten times, then soil erosion would be 100 times and material transported will be increased to the good figure of a million. We have very big engineers, experts on building dams, they do not know these things. Everything is mentioned in this Book and I feel like reading it But I check myself because I have other matters to deal with.

Now in what condition are we? Here we find that velocity is creating havoc Rains fall on the earth and this is like bombardment. Our first line of defence will be these millions of tremulous green leaves of the forests on the catchment area. If the catchment area is denuded of trees, what will happen? The rain will fall

[Shri H. P. Chatterjee]

on the earth directly and it has been established by science that if water on account of rain falls on earth which is bare trickle by trickle within a few years the surface of the earth would vanish, because the vegetables keep the mineral matter in position. The trees are our first line of defence and we are losing them every year This is the position not only in Bhakra; in DVC it is twice that much. I have toured that area with Mr. Gouri, who was the Chief Soil Conservator It is my hobby Out of the 7,200 square miles of catchment area, a major portion I have toured. These portions are denuded of trees which has brought in havoc. Mr. Gouri pointed out that if you just spent Rs 19 crores you will get an income after ten years of Rs. 1½ crores So, this will be a sort of insurance and, at the same time, you will be able to save the dams. But, what is happening now? On the average annually three acre feet silt comes in one sq mile

Now, we have 25 river valley projects and the catchment area is 3 lakh square miles It is not of my working but the figure is supplied by our experts. In June 1964 I was in Srinagar to attend the soil conservation meeting going on there I do not know whether my hon. friend, Shri Shinde, was there or not then Shri Dasappa was presiding over it. I was the only speaker from amongst Members of Parliament because other Members of Parliament did not attend it. I went alone only because it is my subject. What I found there was that our experts were demanding that at least 10 per cent of the catchment area must be afforested within 15 years otherwise our valuable dams, our national monuments, will vanish in no time and we will have no irrigation. They demanded Rs. 363 crores for that. Here I have that literature. It was supplied there in that conference. I have very little time to open it now; I must hurry up. But here they have pointed out that it is very necessary. Our experts, all unanimously, wanted that.

But what happens? Because they are not the masters—it is the Finance Ministry—some people there in the small room sit who think they know everything and they do not grant the money. What will these people do? They have calculated this and this is not a very unreasonable calculation because everywhere in the world, wherever they have prepared dams, they have reserved 10 per cent of that for afforestation.

Even at Bhubaneswar where on 31st December 1960, a conference of all our States Ministers in charge of agriculture was held, which was presided over by the Union Agriculture Minister, it was recommended that 10 per cent of the money on river valley projects should go for soil conservation work. But profession is one thing and practice is another. Nothing is being done What have you granted? In the Third Five-Year Plan you granted only Rs. 11 crores for all the dams and in the Fourth Five Year Plan you have recommended only Rs. 19 crores How can you expect that the thing will go on?

What is happening? I was saying that for one square mile, it has been found by our experts, the average sedimentation is 3 acre-feet. In this 3 lakh square miles catchment area, what will be the sedimentation? You can very well understand that. It will be near about a million acre-feet. If a million acre-feet sedimentation comes in, half of it at least will go to live storage; that is, 5 lakh acre-feet will be reduced of the total live storage. And the reduction of live storage is a serious matter because one acre-foot of water in live storage gives 1½ acre-foot of water for irrigation. That means, we will lose irrigation potential of 7,50,000 acre-feet

Shri R. Barua: What is live storage?

Shri H. P. Chatterjee: Annually it is that much. To create one acre-foot of water in live storage—here is the calculation of our experts—we require Rs. 600; that is, for 5 lakh acre-feet we are losing annually Rs. 30 crores. If you capitalise that, what will happen? You have taken the life of the dams to be hundred years. That means, it will come to Rs. 3000 crores. Therefore no expenditure should be grudged in protecting these water resources. You are not doing it If you lose so much irrigation potential, why do you run after other projects?

Then, we have got the DVC on the lines of the Tennessee Valley Scheme. There in the T.V A was 54 per cent afforestation, even then they thought that if they did not go in for further afforestation, they would be doomed. There the country is hilly just like what you will see if you go to Hazaribagh and Palamau areas. Here the rocks lose all the soil. There is no cover and the ram bombards. You do not have the first line of defence What is the first line of defence? It is these tremulous green leaves. Millions of leaves will hold millions of rain drops and the forest will just bring the humus there underneath, which will retain the water and all mineral matters Here, I am very much tempted to read what the well-known Hydraulic Engineer, Mr. H. G. Morgan, of the T V A says. He says:

> "Dams are good but if we could raise the underground water table of the Tennessee Valley by only 6 inches, that would mean 26 million acre ft of water—four times as the Norris reservoir (biggest in T.V A.) will hold. Nature would do the storing.'

It has been calculated that 100 sq. miles of tropical or sub-tropical forest would absorb approximately 4 million acre ft. of water, a quantity naif the capacity of Bhakra Dam. Bhakra Dam has got a capacity of 8 million acres, from Ruper to Karachi 1000 miles long, 2 miles wide and 6 ft. deep. As regards silt, there is no afforestation on the hills and your Bhakra Dam is silting up. I cannot fail to read this calculation of Sardar Partap Singh:

> "But the object of writing is not to fix an age for Bhakra dam which is not easy of calculation but to warn that it is most likely to be reduced from a possible 600-700 years to a mere 50 or 60 (not 70) which was the true meaning of the cry, 'Bhakra dam is dying" unless we take immediate remedial action . ."

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up

Shri H. P. Chatterjee: I have yet to speak on many things.

Mr. Deputy-Speaker: You can have 3 minutes more.

Shri H. P. Chatterjee: Give me 5 minutes more

I will not touch many other things. About fertiliser, on an hectare, we use 1|7th of the average world consumption of fertiliser per hectare. This is the lowest in the world. In a sense I do not mind it because if you use more fertiliser in an unscientific way, the land will be spoiled. As Mr. Bennett has said, in the Southern and Western portion of America, they have lost millions of acres of land because of too much use of fertilisers. Our people must be taught the proper use of fertilisers. Don't think our farmers are ignorant. If you go a few miles from Delhi to Haryana, you will find farmers who do not require B.D.Os. to teach them agriculture and all these things. What is happening in our country? There are as many as 130 I.A.S. who come out annually and rule our country; these men think they know everything. Our Prime Minister is guided by the 'Save India

[Shri H. P. Chatterjee]

Club" of 3 I.C.S. men. What do they know? Why not change I.A.S. into Indian Agriculture Service? Let us have technical men; let us link laboratories to fields and let us all go to villages and create proper enthusiasm.

What about price factor? I compare here U.K. and India. For India, a tonne of ammonium sulphate costs Rs. 1752 whereas in U.K. its price is only Rs. 671. In India, single superphosphate is Rs. 1519 per tonne whereas in U.K. it is Rs. 552; sulphate of potassium in India is Rs. 829 per tonne whereas in U.K. it is Rs. 629! muriate of potassium in India is Rs. 619 whereas in U.K it is Rs. 500 Wherever you go, this is the thing that is going on.

The less said about cattle breeding the better I thought of speaking on it because they give us organic manure to the extent of 400 million tonnes of cowdung annually which we burn and which is equivalent to 60 million tonnes of firewood. Why not save this? Without this organic manure, you cannot do anything You have destroyed the forests, and all the humus which can preserve water and mineral matter just like a blotting paper has gone. They can keep the water in storage much more than in Govindsagar

But you have destroyed the forests. When the dams would be choked up, floods will occur hundred fold reminiscent of the times of Noah's Ark. In your vandalism, what are you doing again? You are burning all the cow dung. Why not get for the villages soft coke and electric power for their fuel. Send the electricity there and not to the cities, not for our airconditioning and other things. Send the electricity to the villages. Let us all combine together in this. This is our duty. I belong to no party; I am an independent member, though like all independents, I am a second class Parliamentarian here; according to you I have no worth; till I belong to a party I am happy I could catch your eye. We, independents, represent the whole of India. Let us all combine in this endeavour and carry on this thing. We must put food and agriculture above party and do all that is possible to increase the production.

Regarding the zonal thing, I support Mr. Lobo Prabhu. This zonal restriction must vanish. Let us have the courage of Mr. Kidwai. This zonal thing has become a source of corruption. Let India be one whole. Why should the paddy not go from Bengal or anywhere to Bihar? Bihar does not have the option to buy the food from anywhere nor you will supply them that. You have the bird in the cage and kill it like that; you would not be able to take charge of it in this manner. I do not mind Bengal's paddy going to Bihar or anywhere. As a matter of fact, I found this happen in my district; there is a substitute food; they use grams and other pulses during the ban period but this time they are all exported away to Maharashtra. There should be free trade throughout India. Blackmarket prices should be controlled Also merchants should be controlled, but not like this. Just because the duck is laying golden eggs, you should not open its belly and kill it. Do not kill the merchants. Procurement must be there. There should be procurement from one end to another end of India; every one should have equal chances to buy. The country is one; you should not divide it.

I thank you for having given me the opportunity.

Dr. Maitreyee Basu (Darjeeling): I just want half a minute. I want to ask only one question. I am not trying to make a speech. Just one question. I would like the Food Minister, when he replies, to give a reply to this question. It was suggested by a very important Member on the Congress Benches that agriculture

should be treated as an industry and Gandhiji's Centenary should be celebrated on those lines. I would like to ask the Food Minister whether the Congress Party intends floating a joint stock company for agriculture and if so, are they going to give it to one of the big business agency houses?

Some hon. Members: No, no.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): If she forms a co-operative society, we will make her the Managing Director.

श्री बें० मा० अवथ (जालना) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य और कृषि मन्त्रालय की जो मांगें हैं उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आजादी हासिल होने के बाद अनाज मसले पर तवज्जह दी गई, इसकी अहमियत को पहचाना गया और पहली पचवर्षीय योजना में इस पर काफी ज़ोर दिया गया। थोडी बहुत उसमें हमें कामयाबी भी नसीब हुई। लेकिन इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी अहमियत को नजर अन्दाज कर दिया गया और कारखानों पर, धन्धो पर शासन ने अपना लक्ष्य केन्द्रित कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमारे प्लानिंग कमीशन वालों को अपनी गलती महसूस हुई और उन्होंने यह तय किया कि फूड के मामले में सेल्फ सफिश्येंसी के लिए, ज्यादा जोर एग्रीकल्चर पर देना चाहिए। उसके बाद कुछ तवज्जह उस पर दी गई लेकिन जितनी कोशिश होनी चाहिए थी, उतनी कोशिश इस सिलसिले में हमारे शासन की तरफ से नही हुई। हम चौथी पंचवर्षीय योजना के दरवाजे पर आये खड़े हैं। देश की अनाज के मामले में जो भी हालत है वह सब को मालूम है। हम लोग फूड के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। अनाज हमारे मुल्क में कम पैदा होता है और बाहर से आता है। हर साल हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है। जिस तनासुब से मैं आबादी में इजाफा हो रहा है उस तनासब से हमारा खाद्यान्न नही बढ़ने पाता। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जनता को तकलीफ का शिकार होना पड़ रहा है। इसके लिए बहुत से सुझाव आनरेबल मेम्बर्स की तरफ से आये हैं। मैं भी बाज बातें इस सिलसिले में कहना चाहता हूं। हम दुनिया के दूसरे मुल्को के मुकाबिले में इस मैदान में बहुत पिछड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय 1964-65 में कैनाडा मे फी हेक्टर 13.6 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, आस्ट्रेलिया मे 13.8, अर्जेन्टाइना में 18.6, अमेरिका में 17.7, नीदरलैंड्स मे 47.1 और हिन्दुस्तान में 7 3 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान ऐग्रीकल्चर के मामले मे खुराक के मामले में दुनिया की तरक्कीयाफ्ता मुल्कों के मुकाबले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमको इन तमाम हालात को पेशेनजर रखते हुए इस खुराक की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या करना है यह सोचना चाहिए। यह कोई सियासी मसला तो नहीं हो सकता जो भी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं चाहे वे किसी भी दल के हों वह सभी यही बात कहते हैं। लेकिन कहां तक अमल में आता है यह देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि अमल में ऐसा होता नहीं है। यहां पर हम बातें करते है कि तमाम लोगों को मिल कर फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए लेकिन बाहर जाने के बाद ऐसा नहीं होता। यह बड़े दुख की बात है। हम अमेरिका से गेहूं मंगाते हैं, रूस से मंगाते हैं। दुनिया के दरवाजों को खटखटाते हैं और भीख मांगते हैं अनाज के लिए। यह बहुत बुरी बात है।

[की बें० ना० जाधव]

मेरी अपनी राय है कि हिन्दुस्तान में अनाज की बहुत बरबादी होती है। इन्सान का सब से बड़ा दुश्मन अगर कोई हो सकता है तो मेरी अपनी नाकिस राय में वह चूहा है और अगर हमारी फूड मिनिस्ट्री ने चूहे का प्रबन्ध कर दिया तो हमारा जो अनाज बेकार जा रहा है और जो अनाज खाया जा रहा है चूहों के जरिए से वह बच जाएगा। लेकिन हमारा शासन इस मामले में कमजोर पड़ जाता है। दुनिया के तमाम शासन इस छोटे से जानवर चूहे के मुकाबले में कमजोर पड़ रहे हैं। ...(व्यवधान).. .. .... हां साइंटिस्ट्स भी कमजोर हो रहे हैं मिनिस्टर साहब सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कुछ न कुछ कोशिश करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के आदमी अजीबोगरीब हैं। चूहे को पकड़ते हैं और उसे मार नहीं डालते उसे दूसरी जगह छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि वह चूहा अपनी पैदावार बढ़ाता है। काफी मिकदार में हिन्दुस्तान में चूहे हैं। इस का नतीजा यह हो रहा है कि अनाज खाने वाले इन्सान ही नहीं हैं बल्कि जानवर चूहे और दूसरे परिन्दे वगैरह सभी खाते हैं जिस से अनाज की कमी महसूस हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय! हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चरल रिसर्च का काम बहुत कम हुआ है। जो हो रहा है वह काबिले-तारीफ़ है बाज जगहों पर हो रहा है लेकिन जिस कदर इस मैदान में तहकीकात के लिए गुंजाइश है उस कदर नहीं हो रहा है। मेरी यह गुजारिश है कि इस सिलसिले में माहरीन से मशविरा करना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां साइन्टिस्ट्स की कमी है लेकिन हमें कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये। मैं इस बारे में यह अर्ज करूंगा कि हिन्दुस्तान में बहुत से साइन्स कालेज हैं जहां बोटेनिकल डिपार्टमेंट, बायलोजी डिपार्टमेंट, माइकालोजी डिपार्टमेंट हैं, जिनको इन चीजों की तहकीकात का काम दिया जा सकता है, अनाज के रोग और चूहों को नष्ट करने के बारे में तहकीकात का काम दिया जाये। अगर इस तरह से इन्तजाम किया जाये तो आसानी से तहकीकात का काम हो सकता है और इन कामों पर ज्यादा पैसा खर्च करने की नौबत नहीं आयेगी।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां खेती की नुमाइशें बहुत सी जगहों पर एक्जीबीशन्स होती भी हैं लेकिन हर मौसम में यह मुमकिन नहीं होता है। मेरी गुजारिश यह है कि इस किस्म की नुमाइश कम से कम जिले के मुकाम पर हर साल जरूर होनी चाहिये ताकि किसानों को अच्छे बीज और नये तरीके की मकैनाइज्ड फार्मिंग वगैरह की मालूमात हो सकें। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। इस किस्म की नुमाइशों को देखने के बाद नये तरीकों के बारे में किसान भरोसा करेंगे उनको अपने यहां काम में लायेंगे और फिर उससे मुल्क की अनाज की पैदावार ज्यादा होगी।

तीसरी बात जिसकी तरफ़ खास तौर से तवज्जह दी जानी चाहिये वह यह है कि मैंने अकसर देखा है कि किसान बीज के लिये जिला परिषद्, पंचायत दफ्तर, एग्रीकल्चर आफिस और सेक्रेटेरियट के चक्कर मारता रहता है लेकिन उस को वक्त पर बीज नहीं मिलता। जिसका नतीजा यह होता है कि वह कहीं से भी बीज लेकर बो देता है। मैं इस सिलसिले में एक मिसाल देता हूं—अभी हाल में इजराइल और अरबिस्तान की लड़ाई हुई, इजराइल ने अपने यहां दो-दो, ढाई-ढाई, तीन-तीन मील पर एक इंस्टीट्यूशन कायम की है जिसे हम मल्टीपरपज इन्स्टीच्यूशन कह सकते हैं। वहां पर किसानों को जिन चीजों की जरूरत होती है उदाहरणार्थ बीज, खाद, ट्रैक्टर माहिर का मशविरा वगैरह इस तमाम चीजों को मुहैया किया जाता है। इस तरह से

इलाहन में किसानों के दरवाजों तक उन तमाम चीजों को जिनकी किसान को जरूरत होती है पहुंचा दिया है। अगर इसी तरह से हमारा डिपार्टमेंट, मंत्री महोदय, कुछ पहल करें तो किसानों और मुल्क पर बड़ा अहसान होगा।

एक बात आखिर में और अर्ज करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करने जा रही है। मैं मराठवाड़ा से आता हूं जहां पर कोई इण्डस्ट्री नही, कारखाने नहीं हैं सिर्फ एग्रीकल्चर ही है। वहा की जमीन बेहतरीन जमीन है सोना उगलने वाली हैं जरखेज है, अगर आपने किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इजाजत दी है और वह खोली जाने वाली है तो उसके लिये कोई बेहतरीन बैकग्राउण्ड हो मकती है तो वह माराठवाड़ा की जमीन ही सकती है। मिनिस्टर साहब कहगे कि यह तो आपकी जाती राय है यह तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है कि वह इसको कहां पर बनाना चाहती है। मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि मराठवाड़ा पिछड़ा हुआ है इसलिय आप महाराष्ट्र के शासन पर अपना असर इस्तेमाल करें ताकि औरंगाबाद के मुकाम पर जो कि मराठवाड़े का कैपिटल है, यह कृषि यूनिवर्सिटी कायम हो सके।

हमारे मंत्री महोदय और उनके डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर के सम्बन्ध मे काफी काम किया है लेकिन इन कामो को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। खास तौर से बन्डिग का काम ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये ताकि वर्षा के पानी को रोका जा सके। इससे बावोलियों के पानी की सतह ऊंची ही जायगी और उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। एक सबसे बड़ा इन्सेन्टिव किसानों के लिये अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिये यह हो सकता है कि भाव बांधे जाने चाहियें, उसे ज्यादा से ज्यादा भाव दिये जाने चाहियें इससे वह अनाज की पैदावार की तरफ बढ़ेगा और अनाज की पैदावार बढ़ेगी, अगर ऐसा नही किया गया तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (मेडक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं। अन्न के बारे में डिस्कशन हो रहा है बहन सके बारे में बेहतरीन जानती हैं, लेकिन उनमें से अभी किसी को नही बुलाया गया, उनको बोलने के लिये मौका देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी है, अभी आयेगा।

Shrimati Mohinder Kaur (Patiala): I rise to support the demands of the ministry.

The cut motions tabled by the friends opposite show the gravity of the situation. It also shows that this is a subject which cuts across party lines and narrow alignments. This is a subject which is of vital importance to this country, attainment of self-sufficiency in food, and we are all concerned with it. At the recent Chief Ministers' conference, as I was reading through the conclusions, some very parctical suggestions emerged, and I do hope they will not remain only on paper, but Government will implement them.

Shri P. Venkatasubbaiah (Nandyal): The treasury benches are empty, there is no minister here.

Shri M. N. Reddy (Nizamabad): The discussion is on demands for grants of the Food Ministry, and the concerned Cabinet Minister or the Minister of State is not present.

Mr. Deputy-Speaker: The Cabinet Minister and Minister of State were both present just now, they must have gone for tea.

Shri M. N. Reddy: They were present just now, but they are not present now.

Mr. Deputy-Speaker: I shall see that they come back soon. We should not waste time.

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs (Shri R. L. Chaturvedi): They will return within five or six minutes.

Shrimati Mohinder Kaur: For instance, one suggestion that they have made is that a simplified, unified credit structure should be evolved in the country. The credit structure for the farmers, as you know, is a very cumbrous one. Perhaps you are aware that if a small farmer wants credit from the Government, it takes a minimum of six months to one year to get it First you have to go to the patwari because you have to take the *khasra* number. It is almost like pledging the land to the Government, and he is given a loan against that. From the patwari, it has to be endorsed by the village level worker. From there it goes to the Tahsildar for endorsement. From the Tahsildar it goes to the Agricultural Extension Officer. From there it goes to the Block Development Officer, and from there, for final sanction for even a small credit, it has to go to the Collector. And all this takes at least six months to one year, which is a very unsatisfactory arrangement. The Chief Ministers have drawn the attention of Government to the need for a uniform, simplified credit structure in this country, and I do hope Government will take note of it.

I want to quote an instance to you. The other day I was talking to a man from my own constituency. He had applied for a small loan of Rs. 1100, and he had not crossed the last hurdle, the final sanctioning authority, namely the Collector. He was going to and fro with his application to various people, and he had spent Rs. 200 for getting a small loan of Rs. 1100.

I do not know why there is this glaring discrimination between industrial and agricultural loans. In my own State of Punjab, small agricultural loans to the farmer are made available at a rate of interest varying from 9 to 12 per cent, while for industrial development, loans are made available at a rate of 3 per cent, simple interest. I do not now why this glaring discrimination is made between farmers and industrialists I want to come back to irrigation. In this country we want to go in for high yielding varieties. Irrigation is an important factor. Without irrigation we cannot go for this programme of high yielding varieties in a big way We spent Rs 700 crores on minor irrigation in the last three plans. I strongly urge that the present budget provision under this head should be increased by fifty per cent Unless we give more money and provide more facilities to the farmers by way of minor irrigation projects, we cannot go in for this programme. You are aware that these high yielding varieties could be grown only on wet land because a lot of fertiliser has to be used. I have also said before that loans should be made available to the farmers owning two or three acres of lands.

There are certain impediments which are the causes of stagnation of agriculture in this country. Time and again I have spoken on the same subject of land reforms. A number of other people also have spoken but it has been a cry in the wilderness. Any person who is in possession of land beyond a ceiling which the law has imposed has a particular attitude; his effort will be to take out as much as he can out of that land without putting something back into that land.

Unless there is proper inputs, land will become unproductive. This is one important cause of agricultural stagnation. I shall substantiate my argument. I have spoken before in this House and I want to draw the attention of this hon House to a report submitted by Mr. Wolf Ladejinsky who came to India as a Ford Foundation consultant and he went to the districts in India where we have these package programmes and made a through study of this problem and he came to the conclusion that one of the major impediments, one of the causes responsible for stagnation in agriculture was the implementation of land reforms. When I say so, I also know that there is something which we ought to do We should stop the fragmentation of holdings. We have no law to prevent fragmentation at a certain stage; so it keeps on going and the holdings are getting smaller and smaller and at a certain point it becomes uneconomic If we do not pay proper attention to this problem, a time will come when the entire agricultural land in the country would become uneconomic holding Serious thought should be given to this problem Secondly, about the speedy implementation of the land reform policy, I have to say this They say give the land to the landless. Agriculture is also like any other profession You should have the aptitude, the feel for the land. Every landless labourer cannot become an agriculturist You cannot just take a thousand or two thousand landless labourers and put them on the land because agriculture would not prosper unless the farmer has the aptitude and the feel for the land. What do I find when I go round, because I am connected with several voluntary organisations, is this. People are settled on the land; Government even pays them some money and allots them developed lands. After six months or so, they sell it because they do not have the understanding, the aptitude and the feel for the land. If there is surplus land, it should be distributed.

श्री राम सेवक यादव : (बाराबंकी) आप के पास कितनी भूमि है ?

श्रीमती मोहिन्दर कौर . मेरे अपने नाम में ?

श्री राम सेवक यादव . आप के परिवार के नाम मे । यह जाल बट्टा मैं भी बहुत जानता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: You continue; ignore interventions from there

Shrimati Mohinder Kaur: What I was saying is that when surplus land is allotted to the landless, it should be an economic unit, that should be taken into account. It should not be just a couple of acres It should be an economic unit, where a family can depend for its livelihood It should be an economic proposition and not just a couple of acres.

The hon Member who preceded me—Shri H P Chatterjee—made certain points I fully endorse what he said when he talked about soil conservation, and erosion of soil. I fully endorse and I fully agree with him when he talked of the zonal system. I know I am going to tread on delicate ground here I do not know why the Government have adopted this policy of zonal system; closing the barriers This is one country. I am not in a position to speak about other States, but speaking of my own home State, I want to tell you that this is a disastrous policy that we have adopted. I will tell you that a glut has been created in the market, there was plenty of incentive given to the farmers to grow more wheat, and the farmers in Punjab went in a big way to grow high-yielding varieties of wheat. We have fixed Rs. 70 to 85 for a quintal of wheat What happens? We closed the borders, to Haryana, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh which are the adjacent areas to the State. What happens? There is always a glut. The Food Corporation

[Shrimati Mohinder Kaur]

is not allowed to go directly to procure the wheat in that area, and the State Government has taken the responsibility. I want to tell you that it is not a very satisfactory arrangement.

I also want to draw your attention to the fact that wheat prices have been fixed for Punjab The price of coarse grain is much higher than that of wheat in Punjab, whether it is bajra, maize, jawar or cotton seed Look at the price chart It is very much higher than wheat. I am not exaggerating. What I am telling you is a mere fact As a result of that, the wheat is being fed to cattle, as cattle-feed, because it is the lowest I certainly feel that something ought to be done about it I just want two or three minutes more, Sir Something should be done about it, because, after all, this is one country, and the people across, in Bihar, Uttar Pradesh and in so many other parts of the country are almost on the verge of starvation, and this is mainly because we have narrow, outlook we have closed the barriers. The barriers should be removed; we must not close the barriers It is a very very wrong thing, and I request that serious note should be taken about it.

I will tell you another thing About two months ago, when the Punjab Government came into the zonal system, I wrote to the Chief Minister, when the price was fixed for wheat I hold the Chief Minister in very high esteem; he is a personal friend He was gracious enough to reply to my letter; he took about six to seven weeks to reply to my letter. In that letter he said that he had not only to take care of the interests of the producer but the interests of the consumer also. This was his reply; it was not administrative approach. This was the reply I do not know what it was based upon, because Punjab's economy depends on agriculture. In Punjab, 80 per cent of the people live on land; it has a village economy. Of course, there was a time when we were proud of our industries, but as a result of the reorganisation of Punjab, all our industries went to Haryana. I wish them all luck. But the industries have gone out. There was a sum of about Rs. 500 crores capital which had been invested in the industries in Punjab; there was a great industrial development; an industrial belt was there comprising Faridabad, Sonepat and nearby areas Secondly, on account of the Indo-Pakistan conflict also, the industrialists from the border districts of Punjab, where there were some big industries, have pulled out because of insecure conditions; and now, we only depend upon agriculture and our economy is based on agriculture Therefore, to say that the interests of the consumer has to be taken into account is not a logical argument. I am afraid I do not know what is meant by it

I was reading with great interest the proceedings of the Chief Ministers' conference which has just ended in Delhi It was reported in the press that the Chief Minister of Himachal Pradesh Dr. Y. S Parmar, said that if this attitude persists, they would cut down all the forests and start going in for food production in a big way because they have no other option He also said that the result will be soil erosion and Bhakra into which we have sunk crores and crores, with be silted This is a narrow minded policy. I do feel that something ought to be done and the whole policy ought to be reviewed

After devaluation, the cost of fertilisers has gone up by 25 per cent and at the same time, Government have withdrawn the subsidy on fertilisers. When we talk of practical approach to attain self-sufficiency by 1971, these are the practical things which should be looked into. The whole policy should be reviewed and the price of fertilisers should be brought down.

श्री भोगेन्द्र झा : (जयनगर) : खा सहकारिता और सामुदायिक विकास मंत्रालय की जो बजट मागे प्रस्तुत की गयी हैं उन का पूर्णतः विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सरकार की कुछ इक्की दुक्की गलतियो का उस में समावेश है। बल्कि इसलिए कि आज जो स्थिति देश की है उस में पूरी कृषि नीति इस आधार पर चलाई जा रही है जिस से जो खेती में काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं, वे जमीन के मालिक न रहें, धीरे धीरे उन के हाथ से जमीन सिमट कर कुछ एक हाथों में इकट्ठी की जाये।

यह जो स्थिति है, वह बिलायत मे कुछ हद तक चल सकी है, दुनिया को लूट कर उस ने कुछ हद तक इस को चलाया है और दुनिया की दौलत उस ने इकट्ठी की है। यह नीति अमरीका में भी चल सकती है। लेकिन जो स्थिति जापान की है, उस स्थिति में यह नीति वहां भी नहीं चल सकी है और जो सब से प्रतिक्रियावादी नेतृत्व में चलने वाला ताइवान है उस में भी यह नीति नहीं चल सकी है।

[SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA *in the Chair*].

मैं अभी वाद की बातों में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जैसी घनी आबादी वाला देश इस रास्ते पर चलेगा तो को हमेशा ही हमे खाद्यान्नो के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले सिंचाई मंत्री ने कहा था कि पिछले दस बरसों में चौदह सौ करोड़ रुपये की राशि सिंचाई पर खर्च हुई है। यह भी यहा पर कहा गया है कि उसी अवधि में सोलह सौ करोड़ रुपये का खाद्यान्न अमरीका से तथा विदेशों से मंगाया गया है और यह राशि विदेशी मुद्रा के रूप में देनी पड़ी है। हमारे यहां स्थिति ऐसी है कि लगातार हम घाटे में चल रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री रोना रोते हैं कि हमारे देश में एक साथ इनफ्लेशन भी है और डिफ्लेशन भी है। दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। महंगाई भी बढ़ रही है और कई भागों में अतिउत्पादन की समस्या पैदा हो गई है क्योंकि चीजों की बिक्री भी नही हो रही है। कुछ कपड़े की मिल इस कारण से बन्द हो रही हैं। चूंकि कपड़ा नही बिक रहा है इस वास्ते यह नौबत पैदा हुई है। यह स्वाभाविक भी है। हमारे देश की 75 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है। अगर उसके पास जमीन नहीं है, अगर घर में गल्ला नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है तो कारखाने में तैयार माल बिक नहीं सकता है। इसलिए कभी चीनी का संकट पैदा हो जाता है, कभी कपड़े का संकट पैदा हो जाता है और कभी दूसरा माल न बिक सकने के कारण संकट पैदा हो जाता है। एक तरफ मिल मालिक दाम बढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ क्रय शक्ति के लगातार गिरते रहने की वजह से उनके माल की बिक्री नहीं होती है। इस से हमारी तरह की अर्थ व्यवस्था है वह संकट में पड़ गई है और बढ़ती जा रही है। माल बिक नहीं रहा है और कारखाने एक साथ बन्द हो रहे हैं। दूसरी तरफ इसी सामान के बगैर लोग मुहताज है, नंगे हैं, भूखे हैं, उनके पास दवा दारू के साधन नहीं हैं।

सरकार विदेशों से ट्रैक्टर मंगाने की बात सोच रही है, सोवियत संघ से और चेकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टर मंगाने की बात सोच रही है। वह सोचती है कि कुछ राजाओं और रानियो के जो खेत है उन मे ट्रैक्टरों से खेती हो। इन ट्रैक्टरों की सहायता से एक मिनट के लिए मान लो कि खेती की पैदावार बढ़ जाती है तो क्या इस देश की बेकार और जमीन के लिए भूखी जनता को काम मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी? जनता के हाथ से जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वे छिनते जा रहे हैं। राजा और रानिया यह स्वप्न देख रही है कि जमीन की टुकड़े बन्दी नहीं हो, जमीन की चकले बन्दी हो। हजारों छोटे-छोटे ट्रैक्टर ले कर वे बड़े-बड़े जमीनों के

[श्री भोगेंद्र झा]

चकले बनाये । बाकी जो बहुसंख्यक आबादी है वह बेकार होती चली जाए । हमारे देश में भुक्खड़ों की, भिखमंगों की, बकारों की एक जमायत बनती जा रही है । उस जमायत की क्या हालत होगी । देश के बाजार की क्या हालत होगी । अब वह जमाना नही है जबकि वासकोडेगामा और कोलम्बस विदेशों में जा कर बाजारों का पता लगा लेते थे । आज हिन्दुस्तान के लिए दुनिया का बाजार भी खुला हुआ नहीं है । जहां तक अन्दरूनी बाजार की हालत है, वह भी क्रय शक्ति के अभाव मे सिकुडता जा रहा है । वह बडे नहीं रहा है । देश के करोडपतियों को यह अक्ल भी नही है कि विदेशो मे बाजार ढूंढ़े ताकि माल की देश से और विदेशो मे बिक्री हो सके । अरब देशों के बाजार को ढूंढने की उन को चिन्ता नही है । उन को चिन्ता यही है कि मालिक अमरीका जो है वह किस तरह मे खुश रह सकता है और उस को उस तरह से खुश रखने की कोशिश की जाती है । इसी नीति को वे अपने जरिये तथा अपने अखबारो के जरिये चला रहे हैं ।

उस तरफ के हमारे भाई जब भूमि सुधार की बात पेश होती है तो कहते है कि समाजवाद की ओर हम देश को ले जा रहे हैं । ऐसा कह कर वे हमें अपने भ्रम में और धोखे मे डालना चाहते हैं । लेकिन हम धोखे मे आने वाले नही हैं ; इस सरकार से समाजवाद की कोई आशा हमें नही है । हम चाहते हैं कि पूजीवाद ही चलना है तो इस को आप राष्ट्रीय नीति के आधार पर चलाये, इस तरह मे चलाये ताकि छोटे और मझोले लोगो की व्यक्तिगत पूजी की रक्षा हो सके । दाहिनी ओर बैठे हुए माननीय सदस्यो से भी मैं कहना चाहता हूं कि वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के पुजारी हैं, व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता की बात वे करते हैं लेकिन उन को देखना चाहिये कि आज हमारे देश के लग-भग सात आठ करोड़ परिवार जो खेती पर जिन्दा रहते थे या आधा मुर्दा बन कर रहते थे, जो मेहनत करते थे, अब व्यक्तिगत सम्पत्ति उन के पास नहीं रह गई है, वे बेजमीन हो गए हैं, उन की व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा आप करना नहीं चाहते हैं । आप तो यही चाहते हैं कि वे सम्पत्ति से हाथ धो बैठ । और राजा और रानियों को, टाटाज और बिड़लाज को वह मिल जाए, यही व्यक्तिगत सम्पत्ति के पुजारी हिन्दुस्तान मे रह जायें, उन्हीं के पास सारी सम्पत्ति केन्द्रित हो जाए । जब इन गरीब लोगो से जमीन छीनी जाए, कुदाली छीनी जाए, और वे इस बेदखली का विरोध करने के लिए खड़े हो जायें, अपने घरो की रक्षा के लिये खड़े हो जाये, अपनी फसलो की रक्षा के लिए खड़े हो जाय तो हगामे होते हैं कि नक्सलबाडी हो गया । तब आप को बुखार आ जाता है । यह जो देश का नेतृत्व करने वाले शासक दल के लोग हैं, इन को बुखार आ जाता है । तब एक भूकम्प सा आ जाता है । मैं समझता हूं कि एक ही नीति पर पेकिंग रेडियो और हमारे चह्वाण साहब चल रहे है । दोनो एक दूसरे की मदद कर रहे है । पेकिंग कहता है कि माओ के इशारे पर ये विद्रोही चल रहे हैं और गृह मन्त्री जी कहते है कि आदिवासियों मे तीर कमान और धनुष बाण छीन लिये जाये । क्या इस तरह से देश को आप तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं ? आप को चाहिये कि जिन के पास जमीन नही है उन को आप जमीन दे ।

यह एक बुनियादी सवाल है । यह टलने वाला नही है । खेत में जो मेहनत नही करते हैं जो खेत से दूर रहते है और जिस में लोक सभा के सदस्य भी हैं, बड़े-बड़े अफसर भी हैं, जो कि जमीन को देखते तक नही हैं । जो इस तरह से जमीन के मालिक बने बैठ हैं उन का अगर नाम लिया जाता है तो शासक दल के नेताओं को बुखार आने लग जाता है । मैं चाहता हूं कि कम से कम आप जापान की नकल तो करें फारमोसा की नकल तो आप करें । कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी गई थी कि अभी बीस करोड़

एकड़ जमीन ऐसे लोगों के पास है जो ऊपर के लोग हैं, जो जमींदार हैं, जो खेती नहीं करते हैं। यह स्वयं खाद्य मंत्री जी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तीस एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से अधिक वालों की भूमि 8 करोड़ 20 लाख एकड़ है और दस से तीस एकड़ भूमि 11 करोड़ 70 लाख एकड़ है। जापानी पूंजीवाद एशिया का सब से बड़ा पूंजीवाद है और उस पूंजीवाद के मुताबिक भी अगर आप उस की नकल करना चाहते हैं तो बीस करोड़ एकड़ जमीन अभी लेकर आप जमीन वालों को दे सकते हैं, उन को दे सकते है जो रात दिन मेहनत करते है, सूखा पड़ जाए तो भी घड़ों मे पानी भर कर जा कर सिंचाई करते हैं, कुदाली आदि लेकर अपने खेतों को ठीक ठाक करते है, मेहनत करते है। लेकिन उन मे अधिकांश की अपनी जमीन नहीं है। जहां कान नही है, वहां सोना है और जहा कान है, वहा सोना नहीं है। आज हमारे देश में जमीन के मालिक वे हैं, जो मेहनत नही करते हैं, जो खेत पर नही जाते हैं और जो ट्रैक्टरो की मांग करते है। हम चैकोस्लोवाकिया और अन्य देशो से ट्रैक्टर मंगाने पर रुपया खर्च किया जा रहा है, जब कि हमारी कुदाली और खुरपी बेकार पड़ी हुई है। जब कि हमारे हाथ बेकार पड़े हुए हैं।

16 hrs.

आज आवश्यकता इस बात की है कि जमीन के मौलिक सवाल को हल किया जाए। नक्सलबाड़ी का हौवा खड़ा करने से काम नही चलेगा। हमारा इंडियन पीनल कोड अंग्रेजो का बनाया हुआ है, लेकिन उस के अनुसार भी किसान को यह अधिकार है कि अगर कोई उस की सम्पत्ति या खेत पर हमला करे, कोई उस की बेदखली करने के लिए जाये, तो वह लाठी ले कर उस का मुकाबला कर सकता है। वह नक्सलबाड़ी मे कर रहा है और समूचे हिन्दुस्तान मे करेगा। हम लाठी से किसान के खेत की रखवाली करेंगे और बेदखली का मुकाबला करेंगे। इंडियन पीनल कोड में हम को उस का अधिकार दिया हैं। जिन लोगो को देश की फिक्र है, उन को इस का नेतृत्व करना चाहिए। चीन का हुक्म या माओ का हुक्म हम को इस मार्ग से डिगा नही सकेगा। अगर माओ हुक्म ले कर आयेगा, अगर वह यहां कदम बढ़ायेगा, तो हम तलवार से उस का मुकाबला करेंगे, जैसा कि हम ने किया हैं। लेकिन हम चीन और माओ के हौवे के डर से किसान को उजड़ने नही देंगे, उस को बेदखल नही होने देंगे, खेती को बर्बाद नहीं होने देंगे।

मैं समझता हूं कि देश का बाजार बढ़ाने के लिए क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि पचास करोड़ की आबादी वाले इस देश मे ट्रैक्टर मंगा कर गरीब किसानो को बेदखल करने की बीमारी को न शुरू किया जाये। जब यहां ट्रैक्टर का जमाना आयेगा, तब हम उस का चलायेंगे। लेकिन इस समय विदेशो मे ट्रैक्टर मंगा कर अपने हाथो को बेकार न करे बल्कि किसान को जमीन पर कानूनी हक़ दे कर उस की मदद करे।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है श्रीमती इन्दिरा गांधी की श्रीमती सरकार ने इस देश मे उस की अहमियत को अनुभव नही किया है। इसी लिए सिंचाई विभाग के मंत्री को मंत्रि-मंडलीय स्तर देने की जरूरत नही समझी गई है। सम्भव है कि चूंकि सिंचाई मंत्रालय के राज्य-मंत्री एक विशेषज्ञ हैं इस लिए उन को मंत्रि-मंडल स्तर का मंत्री नही बनाया गया है। मैं समझता हूं कि उस तरफ ऐसे लोग मिल जायेंगे जिन्होंने जिन्दगी भर सिंचाई को अपनी आंखो से नही देखा है। अगर किसी विशेषज्ञ को मंत्रि-मंडल स्तर का मंत्री नही बनाना है तो ऐसे लोगो को ही बना दिया जाये।

यह सरकार खाद देगी, ट्रैक्टर देगी, चकबन्दी करेगी लेकिन पानी नही देगी, सिंचाई की व्यवस्था नही करेगी। पानी के बग़ैर खाद की कोई उपयोगिता नही होगी और उपज नही बढ़ सकेगी। हमे जो रिपोर्ट

[श्री भोगेन्द्र झा]

दी गई है, उस में कहा गया है कि देश में कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, सहकारिता, पेट्रोलियम और वित्त विभागों के कार्य में समन्वय किया जा रहा है,। लेकिन हम देखते है कि इन विभागों में सिंचाई विभाग को शामिल नही किया गया है जिस से सिंचाई के प्रति इस सरकार की उपेक्षा स्पष्ट तौर पर प्रकट हो जाती है।

बिहार सरकार बराबर इस बात पर जोर देती रही है कि केन्द्रीय सरकार या तो कोसी-गंडक योजना को ले ले, जिस से पचास लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी, और या वह उस के लिए बिहार सरकार को रुपया दे। लेकिन केन्द्रीय सरकार कहती है कि उस रुपये से हम अमरीका से बाजरा मंगायेंगे, लेकिन कोसी-गंडक योजना के लिए बिहार सरकार को नही देंगे। हमारे देश मे, गंगा-जमना की तलहटी में, कमला-कोसी की मिट्टी से फसल पैदा करने के लिए इस सरकार के पास रुपया नही है, जिन नोटों को वह छोटा कर के छाप रही है, वे भी नही हैं, लेकिन विदेशों से कर्जा लेने मे इस को शर्म नहीं आती है, कलंक नही मालूम होता है। इस सरकार ने भारत को कर्जखोरों का देश बना कर रख दिया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है रूस से जो ट्रेक्टर मंगाए जा रहे है, वह भी हमारे लिए शर्म की बात है। अगर कोई बुनियादी कारखाना बनाया जाये, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जैसे, सूरतगढ फार्म मे जो उपज बढ़ाई जा रही है, वह हमारी है। लेकिन इस प्रकार बाहर से, चाहे किसी भी देश से—स्वर्ग से या नरक से—ट्रेक्टर मंगाना बहुत बुरी बात है। जब आवश्यकता होगी, तो उन के पुर्जों के लिए हम कहां दौड़ेंगे ?

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कृषि नीति को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। सिंचाई का मसला कोई बहुत बड़ा नही है। उस के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं है। मिट्टी हमारे पास है। कुदाली और हाथ हमारे हैं। हमारा अपना रुपया खर्च होगा। इस लिए सिंचाई की योजनायें चला कर हम डेढ़ दो सालों में अपनी उपज की सात फ़ीसदी कमी को पूरा कर सकते हैं। इस कमी को पूरा करना बहुत कठिन काम नही है। लेकिन इस सम्बन्ध में रुपया न होने और खर्च में कमी का बहाना किया जाता है। एक तरफ़ सिंचाई की उपेक्षा की जाती है और दूसरी तरफ़ खाद के नाम पर अमरीका से सांठ-गांठ की जाती है और विदेशी कम्पनियों की खुशामद कर के उन की अपमानजनक शर्तों को मंजूर किया जाता है।

आज खाद्यान्न के सम्बन्ध मे सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नही है। कभी कभी हमारे खाद्य मंत्री को जब जोश आता है, तो वह कहते हैं कि हम खाद्यान्नों का राज्य-व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन फिर बात जहां की तहां रह जाती है। हम जानते हैं कि इस सरकार के न चाहने के बावजूद वह दिन नजदीक आ रहा है, जब यह देश भूखों नहीं मरेगा, कंगाल नहीं रहेगा, विदेशी कर्जों पर निर्भर नही रहेगा, बल्कि वह खाद्यान्न की एक राष्ट्रीय नीति अपनायेगा। अगर हम लोगों के सहयोग से सम्भव नहीं हुआ, तो इन को उखाड़ फेंक कर, इन को ठोकर मार कर यह देश एक राष्ट्रीय खाद्य नीति को अपनायेगा और आगे बढ़ेगा। वह इन लोगों के भरोसे नहीं रहेगा।

खाद्य मंत्री ने बार-बार इस सदन में यह कहा है कि बिहार सरकार हम से 4 लाख टन अनाज प्रति-मास की मांग कर रही है, लेकिन वह देना सम्भव नही है और हम ने सवा दो लाख टन देने का तय किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जितना अनाज इस सरकार ने भेजने का ऐलान किया है, नवम्बर से अब तक उस में भी सवा दो लाख टन की कमी रह गई है। जून में सवा दो लाख टन जाना था, लेकिन कुल मिला

कर 1,26,787 टन भेजा गया है। बिहार सरकार चाहती है कि वह पूरी तरह से मुनाफाखोरी और महंगाई को रोके, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने जितना अनाज देने का वादा किया है जो बहुत नाकाफी है वह उस को भी देने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार मौके पर ऐलान कर के अखबारों में छपवा कर और फूड मंत्री के कह कर भी अनाज में कमी कर देती है। इस लिए उस के प्रति विरोध का वातावरण पैदा हो रहा है।

बिहार की गैर-कांग्रेसी सरकार के प्रति केन्द्रीय सरकार का क्या रुख है वह इस बात से पता चलता है कि यद्यपि पिछले साल इसने बिहार सरकार को दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया था, जबकि हालत इतनी खराब नहीं थी। लेकिन इस वर्ष उतना अनुदान देने से भी इन्कार कर दिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से यह मांग की जाती है कि गंडक-कोसी योजना को चालू करने के लिए उसको कम से कम पचास करोड़ रुपये का कर्जा दिया जाय, लेकिन केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इस का परिणाम यह होगा कि बिहार के लोग अपने यहां अपनी सरकार के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की इस नीति के खिलाफ "बिहार बन्द" की ओर फिर बढ़ेंगे। आज नक्सलबाड़ी के नाम से इस सरकार को धुत्कार पड़ता है। कल अगर "बिहार बन्द" होगा, तो उस धुत्कार का दायरा और बढ़ जायेगा। हम न भूखों मरने के लिए तैयार हैं और न कंगाल रहने के लिए तैयार हैं। बिहार में जो अकाल की हालत थी, उस को देखते हुए किस मंत्री ने यह खतरा जाहिर किया था कि वहां पर भूख से बहुत लोग मरेंगे, लेकिन बिहार की नई सरकार ने महंगाई और अकाल के होते हुए भी बड़े पैमाने पर मुखमरी नहीं होने दी।

नये खाद्य मंत्री जिस तबके से आते हैं, उस को दृष्टि में रख कर कुछ लोगों के मन में यह भ्रम था कि वह खेतिहर मजदूरों का ज्यादा खयाल करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या खयाल किया है? तीसरी पंच-वर्षीय योजना में सात लाख खेत-मजदूर परिवारों के पुनर्वास की योजना थी जिन में से सरकार के अपनी आंकड़ों के मुताबिक कुल 96 हजार को लगभग आठवें हिस्से की व्यवस्था हो सकी। इस बार श्री जगजीवन राम ने बड़ा जोश दिखा कर पांच वर्षों के लिए 53 हजार परिवारों के पुनर्वास का लक्ष्य रखा है। तीसरी पंच-वर्षीय योजना में 7 लाख खेत-मजदूर परिवारों के पुनर्वास की योजना थी और चौथी पंचवर्षीय योजना में 53 हजार परिवारों के बारे में योजना बनाई गई है। यह तरक्की हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेत मजदूर इस स्थिति में बैठे नहीं रहेंगे।

आज देश को पूर्व पश्चिम और उत्तर की ओर से खतरा है और सबसे ज्यादा खतरा है अमरीकनों का, जो नागालैण्ड में उपद्रव करते हैं, जो काश्मीर पर हमारे अधिकार को नहीं मानते हैं जो आज तक गोआ, दमन दीव पर हमारे कब्जे को नहीं मानते हैं। इन सब खतरों का मुकाबला केवल कुछ बड़े लोग नहीं करेंगे। इन का मुकाबला करना होगा पचास करोड़ लोगों को। इसके लिए यह आवश्यक है कि हर आदमी को हर खेतिहर परिवार को जमीन मिले ताकि वह अनुभव करे कि कम से कम एक घर मेरा है, यह समूचा देश मेरा है—मेरा भी है और हमारा भी है। खास-तौर से ऐसा कोई भी आदमी बेघर बेजमीन न रहने पाए जो खेती पर जिन्दा रहता है, तो खेतों पर मेहनत करता है।

अगर यह सरकार अब भी इस बुनियादी नीति को अपनाए तो मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करूंगा, वर्ना मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि इस मंत्रालय की मांगों को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया जाये। उन का पूरी तरह से विरोध किया जाये। उस तरफ के जो सदस्य पहले आलोचना कर के आखिर में समर्थन कर गए हैं वे उन से भी यह आग्रह करूंगा कि वे भी इस विरोध में शामिल होने की हिम्मत करें।

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): Madam Chairman, I am thankful to you for allowing me to intervene in this debate. A number of hon. Members have participated in this debate. About 13 speakers have preceded me and a number of useful suggestions have been made from all sides of the House.

I must say that the tone of the debate and the sincerity with which the Members have spoken has really impressed me. I may not agree with all the views expressed by the Members But I must say that from all sides of the House a concern has been expressed about our agricultural production and a number of useful suggestions have been made in this regard.

Before I go into some of the major issues raised in this debate, I would like to refer to some of the suggestions and points raised by the Members Shri Yajna Datt Sharma—I think he is not here—raised a very important point that food problem, agricultural problem, should be treated as a national problem and that it should be treated above party politics I think, he has expressed the true sentiments of this House as well as of the whole country. I am thankful to him for saying this. I wish party differences do not come in solving our food problem and agricultural problem

Then, Shri Randhir Singh—he is also not here—made a suggestion about the crop insurance. This subject is being debated for quite sometime. I may inform the House that some active steps have recently been taken in this regard. A Bill has been drafted and has been circulated to State Governments and as soon as the comments and the observations of the State Governments are available, we shall introduce the Bill in this House. We are very anxious that, if possible, the Bill is introduced and passed in the current session of Parliament.

An Hon. Member: If possible.

Shri Annasahib Shinde: Once we introduced the Bill we shall be in the hands of the hon. Members.

Shri Ram Kishan made a number of valid points in his speech. He referred to self-sufficiency, price policy and other things. He raised one very important point that agriculture should be treated as an industry. I appreciate his sincerity in giving importance to agriculture The thinking of the Government also on this point has been on similar lines. Unless we look into the economics of agriculture, unless we give adequate importance to price policy that is to be followed in regard to agricultural commodities, I do not think it will be possible for us to solve the problem of agricultural production. I very much appreciate the suggestion made by Shri Ram Kishan in this regard.

Shri H. P. Chatterjee, a very senior Member of this House he has a lot of experience; I have all respect for him—spoke with some feeling and he referred to soil and water conservation I know this is of great importance because unless we conserve our soil, unless afforestation measures are taken, I do not think it would be possible for us to have an integrated development of agriculture Soil conservation and afforestation occupy a pivotal position in the development of agriculture. I may say for the information of Shri Chatterjee that during the Third Five Year Plan, we had tried to have soil conservation and afforestation on about 10 million acres under the State Plan and about 7 lakh acres under Central Plan Similarly, about reclamation of ravines, about 36,000 acres of land were reclaimed in the ravines and about 100,000 acres of alkaline land had also been reclaimed. 16 million acres of dry lands have been brought under conservation farming measures, and for the coming years, we are having a still larger plan for soil conservation

Mr. Chatterjee also referred to the Indian Agricultural Service. I think, he made a very important point about this Government have realised the importance of this because unless agricultural services are raised to the level of the other services unless they are given due importance in our administrative set-up, it will not be possible for us to have the proper status of agriculture recognised in our national life That is why, the Government of India has taken the decision to form an Indian Agricultural Service and active steps are being taken to implement this decision.

I was glad to find that a number of members referred to the high-yielding varieties programme; a number of suggestions were made and a number of words appreciating the programme were said on the floor of this House But some members also expressed some doubts about this programme Particularly, Shri Sharma expressed some doubts about this programme I wish to dwell on this subject at length, but before going to that subject, I would like to mention this

The last two years were the most difficult years from the point of view of agriculture If I may say so, even the notorious Bengal Famine year pales into insignificance if we take into consideration the calamitous effect the last year's drought had on our agricultural production I was just looking into the figures of production that we had in 1940-41 and 1941-42, i.e., just before the Bengal Famine; there, the fall in production was 14 lakh tonnes. But, if the similar production figures of Bihar are looked into, we will find that there has been a steep fall in production; from 75 lakh tonnes in 1964-65 the production in Bihar came down to 69 lakh tonnes in 1965-66, and again from 69 lakh tonnes, it came down to 45 lakh tonnes in 1966-67. What a steep fall! It is much more than what we had during the Bengal Famine year. Though we had such a difficult year, hon. members will appreciate that our people faced the hard situation, the difficult situation, very courageously. All the State Governments—Bihar, U P., M.P., and all other State Governments—were very generously helped by the Centre. An hon Member raised a point about the assistance rendered to Bihar. May I say for the information of the hon Member that the largest amount that has been disbursed was disbursed to assist Bihar in fighting the drought conditions, in helping Bihar in their agricultural production programmes. For instance, during the last year, and during the last few months, the total amount that has been given to Bihar is about Rs 67 crores; for Gujarat, it is Rs 44 crores; for Madhya Pradesh, it is Rs 29 crores; for Rajasthan, it is Rs 20 crores; for West Bengal it is Rs 12 crores; for Uttar Pradesh, it is Rs 7 crores This will indicate to what extent the Centre has gone to assist the State Governments in fighting the drought conditions But the more important point was the response of the people Though the times were very difficult, though we were passing through a very difficult time, the way in which our people faced the difficulty should be appreciated. I must say that the morale of the people either in Bihar or in any other drought-affected area, was very high, though considerable human distress was there, our cattle wealth also suffered; even then, our people did not lose the confidence They responded well to the call of the State Governments as well as to the call of the Centre and they fought this danger very bravely. Our rural community, our farmers in the drought-affected areas, really deserve to be congratulated on facing such a serious crisis very bravely and courageously

Irrigation, seed, credit, fertiliser, agricultural machinery, plant protection measures, marketing, storage, incentive price—all these factors have an important bearing on agricultural production. But the most important of all these factors is the human factor, the human material. I must say

[Shri Annasahib Shinde]

that amongst many countries we have the finest human material in our rural community.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu): Specially farmers.

Shri Annasahib Shinde: Yes. Our farmers are not only intelligent and hard-working but they respond extremely well to new scientific ideas. That has been the experience in the last few years.

I was recently reading a book on agriculture in UK and I found that though we consider UK as one of the advanced countries of the world, even now there are farmers there who do not use chemical fertilisers at all and many of them do not know modern techniques. All the world over, it is our experience that transformation from traditional agriculture to modern agriculture is a long process. But if we look at the development in our country in the last few years, we find that our people are responding to new ideas so well that one really fails to understand how is it that they are responding so well. For instance, I may take the use of fertilisers. A number of Members referred to the importance and use of fertilisers, chemical fertilisers.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): First water, then fertiliser.

Shri Annasahib Shinde: I am coming to water too. I know the hon. Member is very anxious about irrigation. I entirely agree with the sentiments expressed by hon. Members on the floor of the House that minor, medium and major irrigation, all these need to be emphasised and we should accord high priority to these programmes.

Shri Madrika Singh (Aurangabad): That is the basis of the whole thing.

Shri Annasahib Shinde: About 12.8 million acres have been benefited by minor irrigation during the Third Five Year Plan.

Shri Piloo Mody (Godhra): During the First Five Year Plan?

Shri Annasahib Shinde: In the Third Plan period alone. The increasing importance we are attaching to minor irrigation can be seen from the fact that in 1966--67, we brought under minor irrigation alone 3.4 million acres. For 1967-68, we have an ambitious plan, and outlay to the tune of Rs. 102 crores has been provided.

Shri Piloo Mody: What about water-logging?

Shri Annasahib Shinde: A number of things are there. He should allow me to proceed.

श्री भोगेन्द्र झा : इन 20 वर्षों में बिहार मे माइनर इरिगेशन पर कितना खर्च हुआ और वह इस सूखे मे कितना काम आया ।

Shri Annasahib Shinde: I have information with me. I am prepared to pass on the details to him.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): There is one thing. Minor irrigation potential created is not serving its purpose. They have almost dried up.

Shri Annasahib Shinde: Some wastage is necessarily involved. Some wells dry up. But the wastage is not very high. The utility of minor irrigation has been accepted by all in this House as well as outside and I do not think we should say anything against this programme.

Shri Sheo Narain (Basti): It is the best scheme.

Shri Piloo Mody: Nobody is saying anything against it.

Shri Annasahib Shinde: I was referring to the response of our farmers to new ideas. I was mentioning as an instance the use of fertilisers. A few years back, in 1961-62 we hardly utilised about 2.5 lakh tonnes of nitrogenous fertiliser, 0.6 lakh tons of phosphatic fertiliser and 0.2 lakh tonne of postassic fertiliser. As against that this year we are expected to use about 13.5 lakh tonnes of nitrogenous fertiliser, 5 lakhs tonnes of phosphatic fertiliser and about 3 lakh tonnes of potassic fertiliser. By 1970-71, our plan is to use about 24 lakh tonnes of nitrogenous fertiliser, 10 lakh tonnes of phosphatic fertiliser and about 7 lakh tonnes of potassic fertiliser.

Shri Gadilingana Gowd (Kurnool): In spite of so much use of fertiliser, why is there so much food scarcity?

Shri Annasahib Shinde: The point I was driving at was that our farmers are responding so well to new ideas whereas even in some advanced countries farmers, because of their backwardness, do not use fertiliser. But in our country the farmers are so much enlightened that the demand for fertiliser is going up.

Shri Piloo Mody: We all agree.

Shri Annasahib Shinde: I was mentioning that the availability of fertiliser is manyfold as compared to a few years ago; even as compared to last year, we are increasing availability by 50 per cent.

Shri J. B. Kripalani (Guna): What about the response of Government to the needs of the people?

Shri Annasahib Shinde: We are trying to meet the requirements of the farmers by providing these inputs.

Some hon. Members raised the issue of price. Sometime back I had also referred to this. The Government of India have appointed the Agricultural Prices Commission to advise them in regard to agricultural Prices. Though Government use the recommendations of the Commission, in many instances they go steps ahead. For instance, this year the Commission recommended that the procurement price of wheat for Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana and UP should be between Rs. 57.5 to Rs. 65 5 per quintal while actually the prices which have been approved and at which State Governments are procuring now are: Rajasthan Rs. 77—85....

Shri Somavane (Pandharpur): Abolish that Commission.

Shri Annasahib Shinde: . . .Madhya Pradesh Rs. 65—77, Punjab Rs. 70—75, Haryana Rs. 70—75 and UP Rs. 80-85, all per quintal.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah): So Government agree that the Commission's recommendations are not scientific and realistic.

Shri Annasahib Shinde: The hon. Member may have his views on that. I was saying that the sentiment repeatedly expressed on the floor of the House that farmers should be given a very reasonable price, an incentive price, is reciprocated by Government.

Shri Piloo Mody: Parity price.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Can he say the same thing about cotton?

Shri Annasahib Shinde: I know there are some problems with regard to cotton. We can discuss it separately. Unfortunately, it is dealt with by another Ministry, the Commerce Ministry.

Shri Gadilingana Gowd: What are the rates fixed by the Commission for procuring paddy in Andhra Pradesh?

Mr. Chairman: Since he referred to some States, Members from other States want to know about theirs.

Shri Annasahib Shinde: Paddy prices for the kharif season would be determined now for Andhra. The prices

[Shri Annasahib Shinde]

which are now being paid in Andhra are last year's prices. We will get fresh reports from the Agricultural Prices Commission; further, costs have gone up during the last one year, so we will have to take all those factors into consideration before fixing new prices.

Shri Gadilingana Gowd: When it was possible for you to fix for other States, why not for Andhra also?

Shri Annasahib Shinde: I was referring to the fact that we should really try to become self-sufficient as early as possible. The present position is not really very happy, and I quite agree with the sentiment expressed on the floor of the House that we have to import food from 12,000 miles. Even the little West Asian crisis has created difficulties in regard to the availability of food This position, if it continues, has a lot of dangerous implications. The earlier it is ended the better. That is why the Government of India has declared its intention not to have any imports from 1970-71.

Shri Inder J. Malhotra: Don't raise false hopes You have been saying the same thing so many times in the past. and every time you have failed

Shri Annasahib Shinde: Let us try, it is worth trying I am not prepared to say they are false hopes This is based on very sound assumptions, to which I am going to make reference.

The main plank in our new approach is the high yielding variety programme, use of new genetic material which we are trying to popularise among the farmers.

Sharmaji while speaking yesterday asked why should we think of importing seed from outside or getting ideas from outside? I do not think in regard to science we should have any sort of prejudice. We never enquire who invented the motor car, but we are using it in India; we never enquire who invented the radio, but we are using it. Similarly, in the case of seeds, we should not have these outmoded ideas now. Wherever advance has been made in science, we should try to utilise it to our benefit. It is a common practice nowadays to exchange breeding materials between countries. Our young scientists are doing a really good job in this respect. I must say that our young scientists have made outstanding contributions during the last three or four years especially which deserves to be recognised by this House, and I really congratulate our young scientists for the outstanding contribution they have made in developing a number of new strains.

An hon Member: Many are unemployed

Shri Annasahib Shinde: They will be employed

Many of our members have a wrong impression that all those are hybrid. Wheat is not hybrid.

Shri Lobo Prabhu (Udipi): The Minister is no doubt very pleased with himself Let him kindly endeavour to meet some of the criticism of his Ministry.

Shri Annasahib Shinde: Perhaps my senior colleague will reply to the other points I have no time, otherwise I would have met all the points.

Shri Piloo Mody: If he intervenes in the debate, it must not be to praise the engineers, praise the farmer, praise the young scientist. We want to know about food. Soon he will be praising parliamentarians and finally the Ministry.

Shri Annasahib Shinde: I will try to meet some of the points raised by the hon. member. New strains of wheat, paddy, maize and bajra have been introduced recently and they have not only become very popular

but this year we have also a programme for introducing all these various improved seeds in an area of 15 million acres Because of the popularity of the programme, States have come forward to have even bigger programmes if seeds and fertilisers could be assured The per-acre yields which we are having as a result of the adoption of the new programme are so promising that they have opened up new possibilities. We have to see this from two angles. A large number of farmers in our country are small farmers; sixty per cent of our operational holdings are less than five acres according to a recent national sample survey. Because of the high yielding varieties most of these small holdings which we considered uneconomic previously will cease to be so because we can have 4,000—6,000 lbs yield per acre or 5,000—7,000 lbs. per acre A small farmer had less marketable surplus and less left with him for reinvestment for improvement of land. With this new possibility, the small holder can hope to have a reasonable income and a reasonable standard of living The hon. Members of this House should help create consciousness in the country so that this programme becomes more popular

I wish to say something about the contribution that has been made by our scientists in developing these varieties because it must be put on record It would not have been possible to undertake this programme without the valuable contribution made by the scientists. We could give impetus to this programme because our efforts were backed and supported by the research scientists. All are now aware of the great scientific breakthrough which has recently taken place in increasing the yield potential of our major cereals and millets. Geneticists have destroyed the barriers to high yields in wheat, rice, jowar, bajra and maize. These developments arise from the re-patterning of the architecture of these crop plants, so as to make them more efficient in the utilisation of sunlight, water and fertiliser. The pace of progress in the exploitation of research results would be clear from the fact that it was only during the rabi of 1963 that the Mexican wheat was introduced in our country or the first time. In 1966-67, we have about a million acres of land under Mexican wheat. There is probably no parallel in the world for such a rapid progress in the assessment, testing, multiplication and spread of new varieties. In wheat our scientists have now produced several selections from the material received originally from Mexico which combine high yield with desirable grain appearance and quality. Also over 10,000 crosses have been made between the Mexican and Indian wheats and there are many new varieties on the breeders' assembly line Seeds of some of them such as Sona 227, Sonalike, Kalyan 227 and Sharbati Sonora are under large scale multiplication now. High yielding varieties of pulses and oilseeds are also under development. An African groundnut variety has proved to be very high yielding and, last year seeds of this variety were imported from Tanganyka by the National Seeds Corporation Outstanding varieties of pulses are now in an advanced state of testing in a programme of research initiated in 1966 with the collaboration of the US Department of Agriculture It is hoped that varieties, agronomic practices and bacterial cultures which will help to double the average yield of major pulse crops would become available next year. Similarly, attention is being paid to cotton and other commercial crops and all-India co-ordinated research projects have been initiated by the ICAR in all the major crops

Now, the hon Member, Shri Lobo Prabhu while interrupting me, said that I was not trying to reply to some of his queries. I know that the hon. Member has altogether different views. I do not doubt it; he may be honestly holding those views. But I do not agree with him, and I do not think the majority of the population of this country agrees with him on land

[Shri Annasahib Shinde]

reforms (*Interruption*) He spoke about detention of big landlords The tone of his speech was like that.

Shri Lobo Prabhu: Please refer to my words, not to my tone.

श्री राम सेवक यादव : ये बोलते हैं जो कुछ आप उसी पर अमल करते हैं। इतना ही फर्क है। ज्यादा फर्क नहीं है।

Shri Annasahib Shinde: I would only say to Shri Yadav that we have been insisting, requesting the State Governments that they should really, rigorously implement the land reforms. I know that Shri Yadav's party is a partner in many of the State Governments I wish Shri Yadav prevails on the State Governments to implement the land reforms expeditiously We will help them If any State Government wants our assistance to implement the land reforms, we are prepared to render all the necessary assistance to the State Governments. (*Interruption*). Then, the hon. Member, Shri Lobo Prabhu, raised a point that controls are inhibiting production. He made a point that whenever controls were imposed, production had gone down. I humbly differ with him. I disagree with him, because the facts do not corroborate what he has said.

Shri Lobo Prabhu: The figures do

Shri Annasahib Shinde: For instance, in the year 1964-65, it was a year of control, and the highest production of 89 million tonnes was attained by us It was in the year 1964-65. Had the hon. Member's contention been right, then the highest production would not have been attained in the year when we had controls in India.

Shri Lobo Prabhu: What about last year when we had no control?

Shri Annasahib Shinde: Last year's comparison cannot be taken for any purpose, because the hon. Member knows that the last two years were the periods when large tracts of our country were affected by drought, and I do not think we should compare the drought years with normal years

Shri Lobo Prabhu: May I intervene and say that the 1966 figures were the relevant figures?

Shri Annasahib Shinde: Controls were lifted in the year 1952-53. The hon Member, Shri Lobo Prabhu, will kindly attend to me, because he interrupted me. In the year 1952-53, controls were lifted during Shri Kidwai's period The index of production in 1952-53 was 101. Then, it went to 119 when there was no control it came down to 115. How can you explain it? It does not mean that simply because the controls were there, production has gone down. (*Interruption*). In fact, the main point which hon. Members over there were insisting upon is free trade The hon. Member there stands for *laissez faire* in regard to free trade.

Shri Piloo Mody: Do you know the meaning of that word?

Shri Annasahib Shinde: I know Mr. Mody alone has the privilege of knowing the meaning of these words! But may I say, the public opinion in this country wants that for the protection of the common man, for the protection of the poor consumer, for the protection of the farmer, the Government must necessarily intervene and come to their help. (*Interruption*).

For instance, immediately after the Bengal famine, a commission was appointed to go into the causes of the famine and to suggest possible remedies to prevent further tragedy. It was pre-independence period and they were not politicians. Even that Commission suggested that the State must play a positive and vital role in the

foodgrain trade. May I read an extract from that report?

"The State should recognise its ultimate responsibility to provide enough food for all. We enunciate this here as a broad principle, the implications of which emerge from the report as a whole. In India the problem of food supply and nutrition are fundamental and must at all times be one of the primary concerns of Central, Provincial and State Governments. It is abundantly clear that a policy of *laissez faire* in the matter of food supply and distribution can lead nowhere and would probably end in catastrophe All the resources of the Government must be brought to bear in order to achieve the end in view ...".

The Foodgrains Enquiry Committee of 1957, with which Mr. Asoka Mehta was associated also recommended that there should be a progressive socialisation of trade. Perhaps Mr. Lobo Prabhu may say that Mr. Asoka Mehta was a politician. (*Interruptions*).

16.47 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Deputy-Speaker: For a fruitful debate, if there are certain points, you can ask a question. But if several members interrupt, it would be very difficult. I want to regulate it. Let us maintain the dignity of the House

Shri Annasahib Shinde: I wish to draw the attention of the hon. member to the recent report of the Foodgrains Policy Committee Dr D. R. Gadgil who is a member of the Rajya Sabha and some economists were associated with this committee which submitted its report as late as 1966. This committee also has made a recommendation which goes against the views of Shri Lobo Prabhu. I will read an extract from that report:

"....In order to achieve the basic objectives of food policy, it is necessary for Govt increasingly to acquire a large share of the foodgrains produced in the country. It is in the light of this requirement that system of procurement and regulations affecting private trade have to be formulated and appraised Govt, it is obvious, has to strengthen its own machinery for the procurement, transport and distribution of foodgrains in surplus as well as deficit areas. It would be only natural in this context to expect of a public agency like the Food Corporation of India to play an increasingly important role in the implementation of the National Food Policy."

Therefore, public opinion as well as expert opinion differ from the views expressed by Mr Lobo Prabhu I do not think I need advance any additional arguments in support of my contention

Shri Piloo Mody: These are opinions; not facts

Shri Lobo Prabhu: Nor figures.

Shri Annasahib Shinde: I know the views of the Swatantra Party. Though I have respect for the hon. members of that party individually, I differ from their views. I feel that a free trade policy in a country like India will land us in trouble Sometimes the prices may go down and the farmers will suffer Therefore, unless there is a public agency to intervene in the food trade I do not think the interests of the farmers will be protected. (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker: You have a right to embarrass the Government by quoting what they said in the past. Have Government no right to quote what the hon members said? He should not get embarrassed

Shri Piloo Mody: I am not getting embarrassed. He does not meet our argument by quoting facts and figures. He is just giving the opinion of some committee.

Shri Annasahib Shinde: It was a committee appointed by the Government of India. I am sorry the hon. Member does not know even this.

Shri Piloo Mody: You stuff the committees with your own people.

Shri Annasahib Shinde: They are not Government people, they are eminent economists.

Shri Piloo Mody: They are people who share your opinion.

Shri Annasahib Shinde: You can make that charge

Some hon. Members referred to various other agricultural inputs. Hon. Members referred to the requirement of tractors. We are trying to lay emphasis on the programme of indigenous production of tractors in our country. We have now a number of private firms who are manufacturing tractors. Their capacity is expected to be to the tune of 30,000 tractors per year by 1970-71 Last year they produced about 7000 to 8000 tractors. This year they are expected to produce 13000 to 14000 tractors. We are thinking of importing about 10,000 tractors from outside. About 2000 tractors have already been imported and about 8000 tractors, 4000 each from Czechoslovakia and USSR, are proposed to be imported and we are negotiating for importing the same.

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): Last time they said that about 20,000 tractors are lying idle for want of spares What happened to them?

Shri Annasahib Shinde: I quite appreciate what the hon lady Member has said. We are aware of the fact that a large number of tractors in the country are lying idle for want of spares This complaint has been voiced on the floor of the House a number of times How we have made adequate foreign exchange available for importing spares. The users themselves can avail of the foreign exchange and established importers also can import under this. Also, in regard to this requirement, we are prepared to consider, if there is any specific difficulty, the suggestions if any that may be sent to us by the State Governments.

While speaking about tractors, I would like to say one thing. A large number of small farmers cannot own bullocks. Nowadays even to own a bullock it requires a big capital. I find *from some of the farm management* studies that 25 to 30 per cent of the farmers do not own bullocks. Unless we make tractors available to the farmers—in what way they should be made available, whether it should be through cooperative organisations or public sector organisations is a matter of detail—we will not be able to make much progress. Our intention is to formulate a scheme whereby service stations should be established all over the country and tractors should be made available to the farmers.

An hon. Member: What about indigenous production of tractors?

Shri Annasahib Shinde: I have already said that about 30,000 tractors are expected to be produced by indigenous manufacturers by the year 1970-71. We are also contemplating to establish a public sector project for the manufacture of tractors in the horse-power range of 12 to 18

Some hon. Members referred to the need of credit. *My colleague would be* intervening tomorrow and he would be dealing with this point I may say only this much, that we have a very ambitious programme to make more credit available. Last year we advanced about Rs. 414 crores by way of short-term loan We wish to expand this programme by Rs. 100 crores more In addition to that, this programme would be supplemented by long-term and medium-term loans from ARC and other agencies.

In the end, Sir, I would only repeat that we are trying to make our country self-sufficient in food, and if hon.

Members would really try to understand the programmes that have been formulated on the basis of good scientific approach, on the basis of a realistic assessment of availability of inputs etc., they will know that we are bound to increase our production in the coming years.

I find that Shri Malhotra is not here. He was wondering whether what we have been saying can be fulfilled. If he looks at the potentiality for production that is being built up I think he will himself feel convinced that things are changing fast. With the co-operation of the farmers and the inputs we make available, this programme of self-sufficiency by the year 1970-71 should succeed. I hope and wish that the co-operation of the House and the Members would be there to implement this programme, to make this programme successful so that our country becomes self-sufficient in the nearest possible future.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Kirutinan.

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, may I. .

Mr. Deputy-Speaker: You keep your powder dry. I will give you a chance tomorrow. We want a balanced debate here He has some difficulties. So, I am accommodating him.

Shri Ram Sewak Yadav: I am leaving Delhi today.

Mr. Deputy-Speaker: You will get your opportunity; you will get every minute due to you.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): The day began with explosion. Let us have all the explosions, if at all, today; let us have a peaceful day tomorrow.

Mr. Deputy-Speaker: All those who are responsible for whatever explosion has taken place, they will at least pass a sleepless night, if they have any regard for the dignity of the House.

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, डी० एम० के० का एक सदस्य पहले ही बोल चुका है और आप उस दल के दूसरे सदस्य को बुला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यह क्या हो रहा है।

Mr. Deputy-Speaker: I have got my own programme. You will get your opportunity tomorrow. Whatever time is allotted to your group, your group will get it.

श्री राम सेवक यादव : मुझे कल यहां नहीं रहना है। इसी लिए मैं ने आप से बार-बार यह रिक्वेस्ट की है। हमारे दल में अभी तक कोई सदस्य नहीं बोला है।

Mr. Deputy-Speaker: He is speaking for the first time That is No 1. Then, you get ample opportunity to speak. On food debate this would be the general approach.

Shri Ram Sewak Yadav: It is not a question of party but some adjustment.

Mr. Deputy-Speaker: Please resume your seat There must be some discipline In the food debate, those who sit on the back benches, those who do not contribute on policy matters but who bring their own experience before the House, I want to give them early opportunity He is one such member. So, please resume your seat.

श्री राम सेवक यादव : मेरा निवेदन है आप हम को समय देंगे या नहीं, इस बात की बहस नहीं है। बहस इस बात की है कि जब सभी दलों को एक बार अवसर दे दिया गया है, तो हमारे दल ने क्या ख़ता की है. .

Mr. Deputy?Speaker: Now, let us try to finish both.

श्री राम सेवक यादव : . .कि आप उस को अवसर नहीं दे रहे हैं और दूसरे दल को दोबारा अवसर दे रहे हैं ?

Mr. Deputy-Speaker: All of you, excluding Swatantra, have addressed a communication that priority need not go with numbers and all that and that all should be accommodated and that on every occasion a particular party should not get the opportunity to start a debate or that a particular order should not be followed As I have explained, if you have any difficulties, I will try to accommodate both before the other discussion starts. Now, let that Member start his speech.

Shri Jyotirmoy Basu (Diamond Harbour): There must be some set procedure for calling members

Mr. Deputy-Speaker: The Swatantra Party and Jan Sangh have time to their credit. But I have told them that I will call them tomorrow. In particular cases, I am making an exception.

Shri Ram Sewak Yadav: Every party has time to its credit

Mr. Deputy-Speaker: He is speaking for the first time. Let him speak first If he finishes in ten minutes, I will give opportunity to the hon. Member also

श्री अटल विहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : आप बाद में श्री यादव को भी समय दे दिजिए।

Shri Kiruttinan (Sivaganja) Sir, I am very thankful to you and to this hon. House for giving me this opportunity to put forward my concepts and suggestions on this elaborate subject. We all know that the problem of food and agriculture is an elaborate and important problem During my maiden speech I have taken this subject because I am purely an agriculturist. I am proud of it, and I also have come from Ramanathapuram district, which is mostly backward in Madras State as well as in India. Sir, it is economically and socially backward but not in politics because out of 17 Assembly constituencies and three Parliamentary constituencies, not even a single candidate of the Congress Party has come out with success

17 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

You know, Sir, Ramanathapuram is also the home district of the All India Congress Committee's President, Shri Kamaraj. The vast area of this district is filled with agriculturists but half the land only is under cultivation and that too produces a single crop. There is no proper irrigation system. Thousands of tanks, minor and major, which were built up during the period of the Pandyas, have not been properly renovated or repaired.

The human resources in my district have not been utilised properly. You may be aware of the fact that our district was once exporting these human resources to foreign countries like Ceylon, Malaya, Burma and Singapore With these human resources those foreign countries have come to profit and they have economically improved. But I am very sorry to state that under our Government now they are importing these human resources from those foreign countries and they have been kept idle, and these precious resources are labelled as Burma repatriates and Ceylon repatriates. This is the condition in my district, Sir. So, I request the hon Food Minister to take acute and urgent steps to implement certain important schemes in our district. If that is done, we can produce a lot of foodgrains for this country.

As far as the food problem is concerned the situation in our country continues to be more critical Our Food Minister has also pointed out recently

Shri Narendra Singh Mahida: On a point of order, Sir. During the Third Lok Sabha the then hon. Speaker had requested hon. Members not to approach the Chair. I have been noticing since the inception of the Fourth

Lok Sabha that hon. Members approach the Chair every now and then to know about their position.

Shri S. Kandappan (Mettur): He is making a maiden speech.

Mr. Speaker: He is not talking about the speech.

Shri Narendra Singh Mahida: I want a ruling on that. Hon. Members should not approach the Chair.

Mr. Speaker: I have said not once but twice in this House that if hon. Members come to the Chair I am not able to attend to the people who are speaking. I am expected to watch the proceedings and what they say and all that. I have repeatedly said on the floor of the House that hon. Members should not approach the Chair but should leave the paper with the Secretary so that it would be passed on to me. It is very embrrassing when they come. But when they come, if I say, "No, please go away", it will be rude and crude. I hope, hon Members, including hon Ministers, will maintain that they do not come directly to the Chair. I entirely agree with you.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): A point of order cannot be raised in a vacuum and take away the time of the Speaker

Shri Jyotirmoy Basu: *The hon.* Deputy-Speaker has called two people from other parties or even more but he has not bothered to call even one of our speakers What is the remedy for that if we leave a chit on the Table?

Mr Speaker: We will give you time tomorrow Shri Nayanar need not worry.

श्री जार्ज फर्नेंडीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, सदन में एक भी मंत्री नहीं, उपमंत्री नहीं, कोई भी नहीं है ।

Mr. Speaker: There is a Minister of State. He is so lean that you do not consider him as Food Minister.

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri D Ering): No, Sir; I am here.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, असल में यह मंत्री लोग ज्यादा बोलते नही तो कोई पह जानता नही । इसलिए यह माथे पर लिखवा ले तो ज्यादा अच्छा हो ।

Shri Kiruttinan: The hon. Food Minister has recently announced that there will be a serious break-down in the supply of foodgrains from the Centre to the States during the last three months of the current year. By the end of September, the Centre would thus have in all 1.6 million tonnes of foodgrains for supply to the States as against 2.85 million tonnes of foodgrains required to fulfil its commitments.

The production of foodgrains also during the year 1966-67 is estimated at about 76 million tonnes But it is very low production when it is compared with the peak production of 89 million tonnes in the year 1964-65 and somewhat better than 72 3 million tonnes in the year 1965-66. All this makes us feel that the outlook on the food front and on the agricultural front is rather grim. During the First and the Second Five Year Plan periods, the total outlay on agriculture, irrigation and community development amounted to Rs. 1551 crores and during the Third Plan period the outlay was to the tune of Rs. 1718 crores It is rather a sad commentary on the planning system that even after our three Five Year Plans, our agriculture has come to a position where our average annual production during the Third Plan is less than what it was in the Second Plan period.

In our country, one hectare of land gives about 1500 kgs. of rice whereas

[Shri Kiruttinan]

in Japan it gives 4800 kgs. and in U.A.R. it gives 5000 kgs. Similarly, we get about 780 kgs. of wheat as compared to 2450 kgs in U.A.R. and 3560 kgs in West Germany

Now, the important question is why there is a stagnation in our agricultural production The first and foremost reason is the well-known extreme poverty of a large number of small farmers in our country That type of families constitute 80 per cent of our rural population. There is no doubt that this extreme poverty has about as a result of their being neglected by the Government for a long time Firstly, the British Government neglected them That at least is understandable. But what a wonder it is, I am sorry to state, that our own Government, the so-called democratic socialist Government, is also totally neglecting those poor farmers. Because of this neglect, our farmers have not received the necessary protection So, there is less production and there is food shortage in our country

To meet the shortage of food, during the past few years, our Government have been importing sizeable quantities of foodgrains for which valuable foreign exchange is utilised. Admittedly, imports cannot be continued indefinitely in view of the tight foreign exchange position Efforts are, therefore, to be made to produce more food wherever possible. For this, the important needs of the farmers should be fulfilled The first one is the need of tools with which he can improve his agriculture. For this, the Government should supply tractors and bulldozers at a cheaper rate. I want to know from the Minister whether the Government is contemplating any such scheme for this purpose.

The second thing is the timely supply of chemical fertilisers in sufficient quantities to farmers according to their requirements. The true role and status of fertilisers in the agricultural process is far more widely understood in India today than that was ten years ago. The intake of fertilisers per block increased from 1315 quintals in 1952-53 to 5273 quintals in 1965-66. In 1966-67, it is estimated that the country is likely to have used 8 lakh tonnes of nitrogen, 3 lakh tonnes of phosphate and 1,30,000 tonnes of potash That too did not cover full requirements But the likely demand during 1967-68 is estimated to be 13,50,000 tonnes of nitrogen, 5 lakh tonnes of phosphate and 3 lakh tonnes of potash It is to be doubled I doubt how the Government is going to meet this demand Anyway, timely supply is essential The Government has also proposed to increase the price of fertilisers Having the procurement policy and having fixed the price of foodgrains, I cannot understand how dare the Central Government to increase the price of fertiliser I request the hon Minister that the price of fertiliser should not be increased. As far as Tamilzhagam is concerned, I want to stress to the Centarl Government that 75 per cent of the Neyveli fertiliser production should be allocated to our State I expect a specific reply to this point.

The next important one is the supply of high-yielding variety of seeds to the farmers The fourth one is the credit facilities. You may have a very impressive set of figures to show that so many crores of rupees have been distributed among the farmers. But if you go into the villages and look into the needs of the really small and poor farmers, you will find that it is on very rare occasions that these men get any sizeable credit Even where credit is available through co-operative societies and panchayat unions, it is an unfortunate fact that the richer and the influential men in the area manage to get the credits. If I can openly put it, Sir, the credit societies are the financial institutions of the

Congress "Pramukhs" for their election purposes. Benami loans have been raised. Misappropriation of funds from the societies are increasing. This is what I would like to mention about co-operative societies. So far as the co-operative societies are concerned, the loopholes in the legal aspects should be tightened up and necessary action should be taken to tap the credits to the poor farmers without any difficulty.

Further, I would like to submit, Sir, that there is no use giving loans which he has got to return after some days with interest There is no use of giving them short-term loans. Long-term credits should be given. The Central Government should not hesitate and should advise the Reserve Bank and other commercial banks to give long term loans to the farmers. More funds should be allocated from the Central Government.

It is also essential to set up certain industries in rural areas, so that they can earn some extra money and supplement their income

Above all, to gear up the agricultural production I would submit that irrigation is very very essential. Without water, no one can produce anything even with all the other facilities such as tractors, chemical fertilisers, better seeds and cheap credit. Sufficient attention should, therefore, be given to this subject. Dr. Khosla, Governor of Orissa, also regretted that, though agriculture and food production are being given the highest priority, irrigation has been neglected. This has resulted from imbalanced and uncoordinated planning. He felt that in the context of acute food shortage and famine conditions all over India, India's prime need of the hour is more water for irrigation. Our Union Minister of State for Education, Mr. Bhagwat Jha Azad, has also recently said:

> "To tide over the food problem, nothing much was required. If adequate irrigation facilities were provided, the country could be self-sufficient in food. But the talk of irrigation was given less consideration than the proposal for fertiliser factories"

So, Sir, the amount allocated for irrigation is insufficient and the hon. Minister should look into this matter carefully.

Sir, I want to say something about community development programmes. The basic objective of the community development programme has been to generate community participation to solve the problems of our villages. To what extent has this been achieved? How many people are really aware of the colossal national effort to modernize the whole range of our rural life? How many have taken advantage of this effort? Who are the people influenced most by this programme? What progress have our villages made in communication facilities and institutional developments? Has the Panchayat Raj taken roots in the political consciousness of the common villager?

In the context of the grave food situation, has the community development programme contributed in any way to set up food production? Has it been of any help to the farmers? The hon. Food Minister should answer all these questions.

Now, I want to say something about State trading in foodgrains. Though I am in favour of State trading, unfortunately, I am unable to support the State trading under the Congress Government. According to the Audit Report, every year, State trading has given a loss account. The total loss during 1962-63 was Rs. 32.57 crores and that in 1963-64 was Rs. 33.8 crores The Ministry gives several reasons for this. The first one is subsidy for foodgrains, and the second one is loss in transit and in storage, and the third one is loss due to theft.

[Shri Kiruttinan]

From the report of the Public Accounts Committee the quantity of foodgrains lost in transit and in storage and due to theft etc. was 42,649 tonnes in 1962-63 and 29,439 tonnes in 1963-64.

In 1963, the Ministry had stated that the amount of foodgrains damaged and rendered unfit for human consumption was 7430 tonnes worth about Rs. 22 lakhs. Up to October, 1965, the loss in transit only, according to the report of the Public Accounts Committee, has amounted to Rs. 22.54 lakhs. While the country is faced with shortage of foodgarins, a very substantial quantity of foodgrains was rendered unfit for human consumption and wasted. This is burning the heart of the people who deserve human sympathy. So, such wastages should be avoided.

Further, Sir, I understand—I do not know whether it is true or not—that the Food Corporation of India, now in Madras, is going to be shifted to Delhi or some other town in the north. Madras is also within this country

Shri Umanath (Pudukkottai): Not Kerala alone, but Madras also.

Shri Kiruttinan: If there is any such proposal, I should like to submit that it should be scrapped. Let Government think of shifting some other head offices from Delhi to Madras Let them render justice and try to win the heart of the people of Tamil Nad.

श्रीमती लक्ष्मीबाई (मेडक) : अध्यक्ष महोदय, आज खाद्य समस्या के सम्बन्ध में यहां पर बहुत कुछ कहा गया है। सब बोलते हैं कि यह बहुत बड़ी समस्या है मगर करते बहुत कम हैं। मिनिस्ट्री वाले सब बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं लेकिन करने की हिम्मत नहीं करते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब जगजीवन राम है— जिनका जगजीवन नाम है—पता नहीं क्या करते हैं, इन को बड़ा सतर्क हो जाना चाहिये।

सब कहते हैं कि जमीन में ज्यादा उगाओ, इरिगेशन का काम बढ़ रहा है, दूसरी सुविधायें बढ़ रही हैं, लेकिन मैं देखती हूं कि बीमारी फिर भी बढ़ती जा रही है। दूसरे मुल्क जितना पैदा करते हैं, अपनी जरूरत पूरी करने के बाद दूसरों को भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहां पूरा ही नहीं पड़ता। दूसरे मुल्क जनसंख्या में कम हो रहे हैं, जबकि हमारे यहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे मुल्कों के लोग आज हमारे पास आ रहे हैं, रोज रंगून से, बर्मा से, सिंगापुर से हजारों लोग भाग भाग कर यहां आ रहे हैं, पूरी दुनिया में से तीस-तीस हजार लोग हिन्दुस्तान में आते हैं, पोपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि उसका असर जमीन पर भी बढ़ रहा है। हर स्टेट में एक्सपेंशन हो रहा है, कल्टीवेबल लैंड को काटा जा रहा है, मेरे पास आंकड़े हैं, ऐसी 12 परसेंट जमीन कम हो गई है, अच्छी जमीन जो सैकड़ों सालों से गावों में खेती के काम आती थी वह तमाम काटी जा रही है। आप तो अध्यक्ष महोदय, बड़े किसान हैं, आप हमारे प्रांत के बारे में जानते हैं . . .

एक माननीय सदस्य : बड़े किसान के पास ज्यादा जमीन है।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : पत्थरों की जमीन है, पानी का इन्तजाम नहीं है, कैसी

आप लोगों के पास है, उतनी नहीं है। पीने का पानी तक वहां नहीं मिल रहा है। अब इन्तजाम हो रहा है। आप इसको नहीं समझेंगे कि सब लोग बड़ी जमीन नहीं रखते हैं।

हम लोग आंकड़े देख रहे है कि जमीन सिंचाई के नीचे लाई जा रही है। हम आप के हाथ में 850 करोड़ रुपये दे रहे हैं। लेकिन उसको आप लोग ठीक से खर्च नही करते हैं। क्या आप कभी भी उसको ठीक से खर्च करने की जिम्मेदारी लेते हैं? नही लेते। मैं आप से सही बात कहना चाहती हूं। जब उधर के लोग बोलते हैं तब आप को कड़वा लगता है क्योंकि वह एग्जेजरेट करते हैं। लेकिन मैं ठीक बात कह रही हूं इतना रुपया हम आप को देते हैं लेकिन उस में से 200 करोड़ तो आप को एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करना पड़ता है। वह किसान के पास नही जाता है। 800 करोड़ रुपये में से आप 550 करोड़ बाहर से फर्टिलाइजर लाने में खर्च कर देते हैं, और 150 करोड़ सब्सिडी मे चले जाते हैं। यह तो आप लोगों की प्लैनिंग है। बिल्कुल बेढंगी प्लैन हैं। यहां पर बड़े बड़े आफिसर्स अपने मुह बन्द कर के बैठ जाते है। लोगों को जाकर एजुकेट नही करते कि किस तरह से काम होना चाहिए। बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते लेकिन सिर्फ इधर उधर के कामों में सारा समय गुजार देते हैं। हम भी यहा बैठते है वह भी यहा बैठते है, लेकिन सही रूप से किसी बात को सोचते नही हैं। उन लोगों की बात पर मुझे एक बात याद आगई। जनक महाराज के समय में एक बार अकाल आ गया। यह नही है कि पहले अकाल नहीं आता था। पहले भी आता था और अब भी आता है। लेकिन जनक महाराज बहुत सिंसियर थे। क्या आप को पता है जनक महाराज ने क्या किया? उन्होंने पूजा करनी शुरू की। महादेवी उनकी सिंसियरटी को समझ कर बोली कि जनक जाओ लोगों की मदद करो। तुम हाथ में हल लो और जमीन को जोतो, उगाओ। तब जनक महाराज हल लेकर गये और जमीन को जोता। जिस से फिर खूब पैदावार हुई। इसी तरह से डिपार्टमेंट के पास जो आफिसर्स लोग हैं वह फाइल्स लेकर कृषि भवन में बैठे रहते हैं। यह नही कि जो उन के पास ट्रैक्टर्स हैं उन को लेकर खेत में जायें और किसानो के सामने मिसाल पेश करे। मैं इस बात को बिल्कुल पसन्द नही करती। मैं तो कहती हूं कि एक एक बड़े अफसर को एक एक स्टेट देना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी वह सम्भालें। जब कोई डाक्टर बनता है तो दवाखानों में रहता है इंजीनियर बनता है तो प्रोजेक्ट में जाकर काम करता है। लेकिन जो एग्रिकलचरिस्ट बनते हैं, पी० एच० डी० बन जाते हैं फारेन कट्रीज से जाकर, वह फाइल लेकर बैठ जाते हैं। यह बहुत बुरी बात है। मैं जानती हू कि आफिसर लोग खराब आदमी नही हैं जो भी हम यहा बोलते हैं उसको वह ध्यान से सुनते हैं। लेकिन उन को जाकर लोगों को अपनी पालिसी को बतलाना चाहिए। मैं तो कहती हू कि जैसे एक मिलिट्री का ब्रिगेडियर होता है। वह पूरी ब्रिगेड को कट्रोल करता है, उसी तरह से एक एक एग्रिकल्चरिस्ट को 25-25 हजार एकड़ के ऊपर रक्खा जाये। और वह उस काम की देख रेख रक्खे। बल्कि मैं तो यहा तक कहती हू कि मिनिस्टर को भी एक एक हफ्ता एक एक स्टेट में जा कर रहना चाहिये तब उसको पता चलेगा कि उन किसानों को क्या तकलीफ होती है।

आपके पास इतना रुपया हैं। आप शहरों में सब्सिडी दे कर मकान बनवाते हैं। ज्यादा पैसा देकर अनाज बाहर से मंगवाते हैं। स्वेज नहर बन्द हो गई है इस लिये दूसरे रास्ते से आप खाद्य वस्तु ला रहे हैं यहा सब्सिडी देकर दूकानें बनवा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं जो देहातों में गरीब

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

लोग रहते हैं जो कि इतनी मेहनत करते हैं अपने हाथ से अपना काम करते हैं वहां पर उनके लिये दूकाने क्यों नहीं बनवाई जाती ? जब भी फेयरप्राइस शाप्स बनवाई जाती हैं तो बड़े बड़े शहरों में बनवाई जाती हैं। मैं कहना चाहती हूं कि या तो गावों में भी दूकाने होनी चाहिए या फिर शहरों में भी बन्द होनी चाहिए। आप खाने वालों के लिये सब्सिडी देते है, बेचने वालों के लिये सब्सिडी देते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर पर जो कि किसानों के काम आता है, आप ने सब्सिडी हटा दी है। किस तरह से उनका काम चलेगा ? यह बिल्कुल गलत काम हो रहा है। इसके ऊपर आप का ध्यान देना चाहिए। आप दूकानों पर जो सब्सिडी देते है उस पर मुझे यह ऐतराज है कि सिर्फ शहरों में सब्सिडी रखने से और दूकान खोलने से काम बिगडता जा रहा है और दूकानों में ब्लैक-मार्केट हो रही है। इस वास्ते गांव वाले गांव छोड कर शहरों की तरफ आ रहे है। शहरों में राशन है, इस लिये सहूलियतें हैं। इस लिये गांव छोड कर लोग चले आ रहे हैं और गांव तबाह होते चले जा रहे हैं। अगर सब्सिडी देनी ही हो तो इधर भी दी जाये और उधर भी दी जाये नहीं तो बन्द कर दी जाये।

हम आंध्र प्रदेश के लोग कितने अच्छे हैं। आप से हमारे चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि दूसरे राज्यो के लिये आप को 6 लाख टन पैडी देंगे। मद्रास, मैसूर, केरल, बिहार वालों को भी खिलाया और मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, उड़ीसा भी है, जिन को आज तक 4 लाख टन दे चुके हैं।

श्री राम सेवक यादव : उत्तर प्रदेश को भी दे दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : उत्तर प्रदेश में आपकी गवर्नमेंट है उन से कहिये।

हम ने 4 लाख टन दिया है और 2 लाख टन बाकी है। वहां पर पानी नहीं है। स्पीकर साहब का इलाका है जहां पीने के लिये भी पानी नही है। हमारे आंध्रप्रदेश में तीन जगहें हैं। कृष्णा-गोदावरी का इलाका है उन के पास तैलंगाना भी है और रायल-सीमा भी है। यह तीनों बडे गरीब जिले हैं। जब बाढ आती है तो हर तरफ पानी भर जाता है। यहां पर साढे पांच सौ करोड रुपया लगा कर बाहर से हमें अनाज मंगाकर खाना खिलाते है, बाढों से हमारी रक्षा करते है, 200 करोड रुपया लगा कर लोगों को फेयर प्राइस शाप में सब्सिडी देते है। हम ने 60 करोड रुपया लगा दिया है, 25 करोड रुपया और चाहिये। हम को यह रुपया दीजिये हम आप का पूरा इन्तजाम कर देंगे। जो जो लोग खाना चाहते है हम उन्हें चावल देंगे इस का हम वादा करते है। मैं जानना चाहती हूं कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती ? आप क्यों मौन बैठ हुए है हम आप से कोई भीख नहीं मांग रहे है। हम लोन मांग रहे हैं। हमें मालूम नहीं होता है कि आखिर सरकार की पालिसी क्या है अनाज भेजने का पहले तो आर्डर दे देते हैं लेकिन जब बाद में पैसा मांगते है तो फिर घुम फुम करते हैं। एग्रिकल्चर मिनिस्टर को मालूम होना चाहिये कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। जो गाय ज्यादा दूध देने वाली होती है उस को ज्यादा चारा खिलाया जाता है। जो कम दूध देती है उस को कम दो। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। जो पेट भर खिलाता हो उस की बात न पूछी जाये, उस के साथ अच्छा व्यवहार न किया जाये।

एक माननीय सदस्य : क्या आप अब कांग्रेस बना रही हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी बाई : यहां पर लोगों को 99 पैसे में चावल मिलता है लेकिन हमें

1 रु० 5 आने में चावल मिलता है । हमारे चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था इस लिये हम चावल दे रहे हैं लेकिन हम को उस के बदले में कुछ तो दो । गेहूं दो, ज्वार दो । हम मुफ्त तो नहीं मांग रहे है आखिर 1 लाख 50 हजार टन हम भी तो दे रहे हैं । हमारी डिमाड शूगर की 12 हजार टन की हर महीने की है । हमारे पास शूगर होती है लेकिन उस को एक्सपोर्ट किया जाता है । हमारे यहां शगर होती है लेकिन हमारे ही यहा वह आधी कर दी गई है । इतनी कमी तो नही होनी चाहिये । हमारा हिस्सा तो हम को मिलना चाहिये ।

फूड एंड एग्रिकलचर को आप रखते है । मै समझती हू कि एग्रिकलचर नहीं है अब फूड ही रह गई है । एग्रिकलचर का मतलब होता है घर मे तमाम सामान रहना रसोई बनाना । फूड होता है टेबल पर सजाना । आपने एग्रिकलचर को छोड दिया है और फूड को ही पकड लिया है । आपने कारपोरेशन बनाई है और ग्यारह हजार लोग उस मे भरती किए है—

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या अपना भाषण कल जारी रखे । अब हाफ इन आवर लिया जाएगा ।

17.31 hrs.

*RETRENCHMENT IN FOREIGN OIL COMPANIES

Shri Umanath (Pudokkottai): Mr. Speaker, Sir, the retrenchment in the foreign oil companies has been going headlong since 1960. So far 9,000 employees have been retrenched and many more are to be axed. Ever since the Damle Committee imposed a slight restriction on the loot of these oil companies, they have resorted to this retrenchment as a way to restore their pre-Damle committee super profits. It goes without saying that it is the Government's responsibility to ban retrenchment as part of their responsibility to prevent the companies' attempts to circumvent the Damle committee's restriction on their super profits but the Government has utterly failed in this regard. Now an enquiry commission has been appointed by the Government. Does this Commission help to resolve this dispute? According to me the appointment of this commission does not at all help to resolve this dispute. What are the crucial issues involved in this dispute? According to me, they are two. One is whether the business and financial conditions of these companies warrant the creation of any redundancy of labour; if not, how to ensure job security against the onslaught of the foreign oil companies? The second issue is, how to compel the management to stop retrenchment during the pendency of the determination of the main dispute? Let us take the question of maintaining the *status quo* during the pendency. It is a sorry tale of the foreign oil companies defying their own assurances, defying the union, defying the government and defying the labour relations. In short it is perpetrating humiliation in this country while the Government just kept looking on, putting up an appearance of helplessness. In 1965, when the first tripartite to ensure job security was appointed, Shri Sanjivayya assured this House that *status quo* would be maintained. The companies trampled under foot this assurance and went on retrenching people. Then again in October 1966, when the Labour Commissioner of West Bengal fixed the conciliation for the 17th of that month, these companies assured that *status quo* would be maintained and got extension of that date upto the 20th. But before the con-

*Half an hour Discussion.